


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आ० 15, 1938

No. 230]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय: चीन जन गण के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सर्टेन ग्लास फाइबर और तत्संबंधी वस्तुओं" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 15/10/2015-डीजीएडी -1. यतः 1995 में और तदोपरान्त यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर और क्षति के निर्धारण के लिए पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद से इसे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 08 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सर्टेन ग्लास फाइबर और तत्संबंधी वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक पाटनरोधी जांच आरंभ की है। प्राधिकारी ने दिनांक 02 जून, 2010 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए और दिनांक 14 जुलाई, 2010 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत अनंतिम शुल्क लगाए थे। प्राधिकारी ने दिनांक 06 जनवरी, 2011 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए और दिनांक 04 मार्च, 2011 को निश्चयात्मक शुल्क लगाए थे। तदोपरान्त, प्राधिकारी ने दिनांक 19 सितंबर, 2013 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध एक मध्यावधिक समीक्षा जांच आरंभ की तथा दिनांक 10 फरवरी, 2014 के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 09 मई, 2014 की सीमा शुल्क अधिसूचना के तहत संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे और क्षेत्र से 0.3-2.5 माइक्रोन तक की रेंज के फाइबर वाले माइक्रो ग्लास फाइबर को निकाल दिया गया था।

2. और यतः मैसर्स औन्स-कॉर्निंग (इंडिया) प्रा. लि. और औन्स-कॉर्निंग इंडस्ट्रीज [इंडिया: प्रा. लि. (इसके बाद से इसे याचिकाकर्ता कहा गया है)] ने प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम और नियमों के अनुसार संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों की ओर से एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दाखिल किया है जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया गया और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है।
3. घरेलू उद्योग की ओर से दाखिल विधिवत प्रमाणित याचिका के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी ने चीन (इसके बाद इसे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "सर्टेन ग्लास फाइबर और तत्संबंधी वस्तुओं" के संबंध में लगाए गए शुल्क को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, दिनांक 07 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 15/10/2015-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या 33/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 13 जुलाई, 2016 सहित इस तिथि तक बढ़ाया गया था।
4. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

ख. प्रक्रिया

5. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. नई दिल्ली में चीन के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार जांच आरंभ करने के संबंध में सूचित किया गया।
 - ii. प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपरोक्त नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय अंश की प्रतियां प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई।
 - iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के सार्वजनिक सूचना की प्रतियां भेजीं तथा उन्हें नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार उसके 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया:
 - i. चोंगकिंग पीलोकॉम्प इंटरनेशनल कारपो.
 - ii. जूशी ग्रुप कं. लि.
 - iii. तैशान फाइबर ग्लास इंक. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन
 - iv. जीबो पीपीजी सिनोमा जिंजिंग फाइबर ग्लास कं. लि.
 - v. शांडोंग फाइबर ग्लास कम्पोजिट मेटेरियल्स कं. लि.
 - vi. चांगझोऊ तियानमा ग्रुप कं. लि.
 - vii. पीपीजी सिनोमा जिंजिंग फाइबर ग्लास कं. लि.
 - viii. चांगझोऊ न्यू चंघाई फाइबर ग्लास कं. लि.
 - ix. जियांग्सू चंघाई कम्पोजिट मेटेरियल्स होल्डिंग कं. लि.
 - x. तैशान फाइबर ग्लास जोउचेंग कं. लि.
 - xi. शांडोंग एस्टे न्यू मेटेरियल्स कं. लि.
 - xii. शांडोंग फाइबर ग्लास कम्पोजिट मेटेरियल्स कं. लि.
 - xiii. सीएनबीएम इंटरनेशनल कारपोरेशन
 - xiv. चांगझोऊ तियानमा ग्रुप कं. लि.
 - xv. चीन नेशनल मेटेरियल्स इंडस्ट्री इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन
 - xvi. शांडोंग तैशान-पीडीओ ग्लास फाइबर प्रोडक्ट्स कं. लि.
 - xvii. सिनोमा जिंजिंग फाइबर ग्लास कं. लि.
 - xviii. झेजियांग जियाशान ग्लास फाइबर वीविंग फैक्ट्री

6. निम्नलिखित निर्यातकों से प्रश्नावली उत्तर प्राप्त हुए हैं:

- i. जूशी ग्रुप जियुजियांग कं. लि.
- ii. जूशी ग्रुप झेजियांग कं. लि.
- iii. जूशी ग्रुप चेंगडु कं. लि.
- iv. चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन
- v. तैशान फाइबर ग्लास इंक.

7. चीन जन गण में ज्ञात उत्पादकों व निर्यातकों तथा भारत में चीन जन गण के दूतावास को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान करने के अनुरोध के साथ बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली भेजी गई थी।

8. किसी भी प्राधिकारी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया है।

9. प्राधिकारी के भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम व पते प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि वे नियम 6(4) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं:

- i. केमराँक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लि.
- ii. पेनटेयर वाटर इंडिया पी. लि.
- iii. अमियनटिट फाइबर ग्लास इंडिया लिमिटेड
- iv. सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लि.
- v. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड
- vi. इंदौर कम्पोजिट प्रा. लि.
- vii. अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड
- viii. बालाजी फाइबर री-इंफोर्समेंट प्रा. लि.
- ix. ओ.के. ग्लास फाइबर लिमिटेड
- x. जूशी (इंडिया) एफआरपी एसेसरीज प्रा. लि.
- xi. स्काई फाइबर ग्लास सॉल्यूशन्स प्रा. लि.
- xii. आरवी कम्पोजिट्स प्रा. लि.
- xiii. कुश सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiv. एडवांस टेक्सटाइल्स एंड मेटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड

10. जूशी (इंडिया) एफआरपी एसेसरीज प्रा. लि. नामक एक आयातक को आयातक प्रश्नावली उत्तर प्राप्त हुआ था।

11. निम्नलिखित उत्पादकों/आयातकों ने एक विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर के बिना याचिका दाखिल की है। इन पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं को भी वर्तमान निर्धारण में शामिल किया गया है:

- i. मैसर्स यूपी द्विगा फाइबर ग्लास लि.
- ii. मैसर्स ऊर्जा प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
- iii. मैसर्स सेयरटेक्स इंडिया प्रा. लि.

12. जांच शुरू होने के बाद जांच आरंभ होने की अधिसूचना की एक प्रति संबद्ध वस्तु के अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादक अर्थात् गोवा ग्लास फाइबर लि. को भी भेजी गई थी। कंपनी ने निर्णायक समीक्षा याचिका का समर्थन किया है और अपनी क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। तथापि, यह सूचना काफी विलंब की अवस्था में प्राप्त हुई थी और मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर लि. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर क्षति के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया।

13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक की है। क्षति विश्लेषण के प्रसंग में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2011-मार्च, 2012, अप्रैल, 2012-मार्च, 2013, अप्रैल, 2013-मार्च, 2014 की अवधि और जांच की अवधि शामिल है।
14. प्राधिकारी ने पाटन के विश्लेषण और क्षति के विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने जांच प्रारंभ होने के समय आईबीआईएस नामित द्वितीयक स्रोत के तहत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और बाद में इसके बाद डीजीसीआईएंडएस के आंकड़े दिए हैं।
15. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश के सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है, जिसे नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा देखे जाने के लिए रखा गया है।
16. प्राधिकारी ने वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार भारत में उत्पादन की लागत का आकलन और संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2015 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भी सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया, जिसका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपयोग किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त उनके विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।
18. जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोध को इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में शामिल किया गया है।
19. भागीदार घरेलू उत्पादकों और संबद्ध उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यकतानुसार किया गया था।
20. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने अपेक्षा के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां-कहीं सम्भव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल सूचना का उपयुक्त अगोपनीय अंश उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।
21. जहां-कहीं किसी पक्षकार ने इससे इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच के पर्याप्त रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने "उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना" का उपयोग किया है और ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है।
22. दिनांक 23.06.2016 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य शामिल थे, जो इस अंतिम जांच परिणाम के लिए आधार बने। प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 29.06.2016 तक का समय प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटीकरण पश्चात की टिप्पणियों पर समुचित विचार किया है।
23. *** इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत स्वीकार गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना को दर्शाता है।
24. प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए विनिमय दर को 61.69 रुपए = 1 यूएस डॉलर माना गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का क्षेत्र

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

25. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:
 - i. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों को निर्यातित उत्पादन में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमतों, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण इत्यादि जैसे मापदंडों के संदर्भ में तुलनात्मक गुण हैं।

- ii. नम कटे टुकड़ों (वेट चोप स्ट्रॉंड) में कोई अलग भौतिक और रासायनिक गुण नहीं होता बल्कि वही गुण होता है जो अन्य प्रकार के ग्लास फाइबर में होता है। इसके अलावा, अंतर भी इतना अधिक नहीं होता कि उन्हें अलग-अलग उपयोग होने से इसे अलग उत्पाद नहीं माना जा सकता कि समान उत्पाद के निर्धारण के लिए एक मापदंड के रूप में इसका प्रतिस्थापनीय उपयोग कभी भी नहीं देखा जा सकता।
- iii. याचिकाकर्ता पहले नम कटे टुकड़ों (वेच चोप स्ट्रॉंड) का उत्पादन कर रहा था और इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारण इसे बंद कर दिया गया है। इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन किसी घरेलू उत्पादक द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए इस उत्पाद के प्रकार का जांच के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।
- iv. मैसर्स औन्स-कॉर्निंग ने यह कहा है कि वे नम और कटे हुए टुकड़ों का निर्माण नहीं कर रहे। मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर लि. ने यह कहा है कि उनके पास शुष्क और नम कटे टुकड़ों का उत्पादन करने की क्षमता है। वे पिछले वर्ष तक नम कटे टुकड़ों का उत्पादन कर रहे थे लेकिन उन्होंने कम लाभकारी कीमतों के कारण से इसे बंद कर दिया है और यदि कीमतें बेहतर मिलती हैं तो वे भविष्य में उत्पादन करने में समर्थ हैं क्योंकि उनके पास क्षमताएं हैं।
- v. एक नया उन्नत ग्लास फाइबर उत्पाद सेमफिल एक "अल्काली रजिस्टेंच ग्लास फाइबर कंक्रीट री-इंफोर्समेंट, सेमफिल" है, जो औन्स-कॉर्निंग का एक ब्रांड नाम है और भारत में निर्माण नहीं किया जाता। मूल जांच के समय, अल्काली रजिस्टेंच ग्लास को अलग नहीं किया गया था क्योंकि इस उत्पाद के प्रकार को न तो संतुष्ट देश से आयात किया जा रहा और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई घरेलू उत्पादन किया जा रहा था। जब तक कि कोई उत्पाद भारत में आयात न किया जा रहा हो, उसको बाहर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, वर्तमान जांच की अवधि में इस उत्पाद को भारत में निर्यात किया जा रहा है, जबकि अभी भी भारत में अल्काली रजिस्टेंच ग्लास के लिए कोई घरेलू निर्माता नहीं है। याचिकाकर्ता ने जांच प्रारंभ करने के समय यह अनुरोध किया था कि इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाए।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- i. मैसर्स यूपी टिवग फाइबर ग्लास लि. ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों के लिए नम कटे टुकड़ों (वेट चोप स्ट्रॉंड) समान उत्पाद नहीं है। वेट चोप स्ट्रॉंड भारत में पाटन किए जाने के लिए जांच के अधीन "समान अथवा अभिन्न वस्तु नहीं है और न ही ये नम कटे टुकड़े" निम्नलिखित कारण से पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) और डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 2.6 के संदर्भ में जांच के अधीन वस्तुओं के सन्निकट गुण रखते हैं:
- ii. वेट चोप स्ट्रॉंड का घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों की तुलना में अलग रासायनिक और भौतिक गुण होता है। वेट चोप स्ट्रॉंड में नमी का अंश 8% से 12% अधिक होता है और शीशे का अंश 88% से 92% तक होता है, जबकि सामान्य तौर पर चोप स्ट्रॉंड में शीशे का अंश 96% से भी अधिक होता है और नमी किसी भी तरह से 2% से अधिक नहीं हो सकती। वेट चोप स्ट्रॉंड और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्लास फाइबर के बीच अंतर होने का प्रमाण घरेलू उद्योग की ग्लोबल वेबसाइट पर प्रदान किए गए विनिर्देशों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है।
- iii. वेट चोप स्ट्रॉंड के लिए उत्पादन प्रक्रिया चोप स्ट्रॉंड की अपेक्षा काफी अलग है। चोप स्ट्रॉंड के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में वैचिंग, मेल्टिंग, फाइबराइजेशन, कोटिंग तथा अन्त में सुखाना शामिल है। तथापि, नम चोप स्ट्रॉंड के लिए प्रक्रिया फाइबराइजेशन की अवस्था से ही अलग है क्योंकि नमी को अंदर रखने की जरूरत होती है और इसीलिए उस पर कोट नहीं लगाई जा सकती और सुखाया नहीं जा सकता।
- iv. वेच चोप स्ट्रॉंड के कार्य और अंतिम उपयोग चोप स्ट्रॉंड से काफी भिन्न हैं। वेट चोप स्ट्रॉंड से फाइबर ग्लास टिशू अथवा वेल्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंतिम उपयोगों में कारपेट टाइल, कुशन, विनाइल फ्लोरिंग, एसफाल्टर रूफिंग, शिंगल्स इत्यादि शामिल हैं। वेट चोप स्ट्रॉंड का उपयोग नम-प्रक्रियाओं और गैर-बुनाई अनुप्रयोगों में किया जाता है। इस संबंध में घरेलू उद्योग की ग्लोबल वेबसाइट के आधार पर साक्ष्य प्रदान किए गए हैं।

- v. ओक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2001 (130) ईएलटी-58] और इंडियन रिफ़ैक्ट्री मेकर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2000 (119)ईएलटी-319 (ट्रिब्यूनल) में ट्रिब्यूनल के जांच परिणामों में यह स्पष्ट किया गया है कि घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित न किए गए उत्पाद, जो विभिन्न ग्रेड/टाइप के हों, पाटनरोधी शुल्क लगाने से बाहर नहीं किए जाएंगे।
- vi. प्राधिकारी, यदि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को सीमित करने की जरूरत प्रमाणित होती है तो निर्णय समीक्षा जांच में उत्पादों को बाहर निकाल सकता है। इस संबंध में, रिलायंस को प्राधिकारी के जांच परिणामों पर चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डक्टाइल आयरन पाइप के आयातों के संबंध में, निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच, यूरोपीय संघ के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी पेस्ट रेसिन के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच, चीन जन गण, चीनी तैपई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड तथा कोरिया जन गण से नाइलोन फिलामेंट यार्न के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में रखा गया था।
- vii. आयातक द्वारा यह कहा गया था कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि वह भारत में नम चोप स्ट्रांड का उत्पादन नहीं कर रहा और यह भी स्वीकार किया है कि नम चोप स्ट्रांड घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों से अलग उत्पाद है। घरेलू उद्योग ने भी यह स्पष्ट किया है कि नम चोप स्ट्रांड को इसकी वर्तमान सुविधा पर निर्मित नहीं किया जा सकता। यह भी कि इसकी भारत में इसकी सुविधा में नम चोप स्ट्रांड का उत्पादन करने की कोई भावी योजना नहीं है।
- viii. आयातकों द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मैसर्स औन्स-कॉर्निंग ने वर्ष 2015 के बाद से सभी अनुप्रयोगों के लिए चोप स्ट्रांड का विनिर्माण बंद कर दिया है। पहले वे थर्मोसेट अनुप्रयोगों के लिए चोप स्ट्रांड का निर्माण करते थे न कि थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए। इसीलिए थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए चोप स्ट्रांड को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया गया था। अब मैसर्स औन्स-कॉर्निंग ने थर्मोसेट अनुप्रयोगों के लिए चोप स्ट्रांड का निर्माण करना बंद कर दिया है और इसीलिए इन्हें भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किया जाएगा।

प्राधिकारी द्वारा जांच

27. विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच में इस प्रकार परिभाषित किया गया था, "ग्लास फाइबर, जिसमें ग्लास रीविंग (संकलित रीविंग (एआर), प्रत्यक्ष रीविंग (डीआर), ग्लास चोप स्ट्रांड (सीएस), ग्लास चोप स्ट्रांड मेट (सीएसएम) शामिल हैं। विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर किए गए उत्पादों में ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, फाइबर ग्लास इंसुलेशन ऊन के रूप में, ग्लास यार्न, ग्लास वूवन फैब्रिक, ग्लास फाइबर फैब्रिक, ग्लास वूवन रीविंग और चोप स्ट्रांड थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों हेतु, माइक्रो ग्लास फाइबर बैट्री सेपरेटर, सरफेस मेट/सरफेस वेल/टिश्यू के लिए।"
28. मध्यावधिक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को "ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, फाइबर ग्लास इंसुलेशन-ऊन के रूप में, ग्लास यार्न, ग्लास वूवन फैब्रिक, ग्लास फैब्रिक, ग्लास वूवन रीविंग, तथा चोप स्ट्रांड-थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों हेतु, माइक्रो ग्लास फाइबर, जिसका 0.3 से 2.5 माइक्रोन तक की रेंज में फाइबर व्यास हो, सरफेस मेट/सरफेस वेल/टिश्यू" को बाहर करके संशोधित किया गया था।
29. प्राधिकारी ने मैसर्स यूपी टिवग फाइबर ग्लास लि. के इस अनुरोध को नोट किया है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नम चोप स्ट्रांड को निकाला जाए क्योंकि घरेलू उद्योग नम चोप स्ट्रांड का उत्पादन नहीं करता। उत्पादन प्रक्रिया, भौतिक और रासायनिक गुण तथा नम चोप स्ट्रांड के उपयोग विचाराधीन से भिन्न हैं। घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित नहीं कर पाया है कि संबद्ध वस्तुएं और नम चोप स्ट्रांड समान वस्तुएं हैं। दोनों ही उत्पादकों को एक विशेष संदर्भ किया गया था जिसमें उनके द्वारा निर्मित की जा रही वास्तविक वस्तु के बारे में पुष्टि करने की मांग की गई थी। मैसर्स औन्स-कॉर्निंग ने यह पुष्टि की है कि वे नम चोप स्ट्रांड का निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर लि. ने यह उल्लेख किया है कि उनके पास शुष्क और नम चोप स्ट्रांड का उत्पादन करने की क्षमताएं हैं लेकिन वे नम चोप स्ट्रांड का उत्पादन वर्तमान में नहीं कर रहे हैं क्योंकि कीमतें गैर-लाभकारी हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी संरक्षण दिए जाने के बाद भी घरेलू उत्पादों ने नम चोप स्ट्रांड का निर्माण बंद कर दिया है, अतः आयातक/उपभोक्ता का अनुरोध इस संदर्भ में सही है कि भारत में नम चोप स्ट्रांड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से, प्राधिकारी ने नम चोप स्ट्रांड को विचाराधीन उत्पादन के वर्तमान दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है।
30. जहां तक थर्मोसेट अनुप्रयोग के लिए चोप स्ट्रांड के संबंध में आयातक की आपत्तियों का संबंध है, मैसर्स औन्स-कॉर्निंग को एक विशेष संदर्भ किया गया था जिसमें कि उनके द्वारा निर्मित किए जा रहे उत्पादों की सूची की मांग की गई थी। मैसर्स औन्स-

कॉर्निंग ने यह पुष्टि की है कि वे थर्मोस्टेट अनुप्रयोगों के लिए चोप स्ट्रॉड का निर्माण कर रहे हैं। इसे देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चोप स्ट्रॉड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ही रहेंगे।

31. किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार ने सेमफिल (अल्काली रेजिस्टेंट ग्लास फाइबर-कंक्रीट री-इंफोर्समेंट हेतु) को बाहर करने के खिलाफ कोई अनुरोध नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पादन के दायरे से इस नए उत्पाद के प्रकार को निकालने का निर्णय लिया है।
32. इस प्रकार, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस प्रकार है:

"ग्लास फाइबर, जिसमें ग्लास रीविंग (संकलित रीविंग (एआर), प्रत्यक्ष सेविंग (डीआर), ग्लास चोप स्ट्रॉड (सीएस), ग्लास चोप स्ट्रॉड मैट (सीएसएम) शामिल है। विशेष रूप से विचाराधीन उत्पादों के दायरे से बाहर हैं, ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, फाइबर ग्लास इंसुलेशन – ऊन के रूप में, ग्लास यार्न, ग्लास वूवन फैब्रिक, ग्लास फाइबर फैब्रिक, ग्लास वूवन रीविंग, चोप स्ट्रॉड – थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों हेतु, माइक्रो ग्लास फाइबर, जिसका फाइबर व्यास 0.3 से 2.5 माइक्रोन के बीच हो, सरफेस मैट/सरफेस वेल/टिश्यू, नम चोप स्ट्रॉड तथा सेमफिल (अल्काली रेजिस्टेंट ग्लास फाइबर, कंक्रीट री-इंफोर्समेंट हेतु),"

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

33. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता के अलावा संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक है, अर्थात् मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर।
 - ii. दोनों ही याचिकाकर्ता औन्स-कॉर्निंग, यूएस से संबद्ध है, जो मूल कंपनी है।
 - iii. याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
 - iv. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए उत्पादन में भारतीय उत्पादन और याचिकाकर्ताओं का बड़ा हिस्सा है, इसलिए पाटनरोधी नियमों के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

34. किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई भी अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

35. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

36. आवेदन मैसर्स औन्स-कॉर्निंग (इंडिया) प्रा. लि. और औन्स-कॉर्निंग इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा दाखिल किया गया था। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में संबद्ध वस्तु का मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर लि. नामक एक अन्य उत्पादक है, जिसने जांच प्रारंभ करने के बाद आवेदन का समर्थन किया है। मैसर्स गोवा ग्लास फाइबर लि. ने काफी विलंब की अवस्था में अपनी सूचना दाखिल की थी और इसीलिए क्षति के निर्धारण के लिए आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से कोई आयात नहीं किया है। आवेदक उत्पादकों के उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा शामिल है और इसीलिए आवेदकों में घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के तहत इसके तात्पर्य में शामिल है।

ड. विविध मामले

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

37. इस संबंध में घरेलू उद्योग के विचार इस प्रकार हैं:

- याचिकाकर्ता ने चीन से विचाराधीन उत्पाद के तहत उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों से ग्लास फाइबर उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों/रूपों का आयात किया है। मात्रा और आयात की कीमत भी नीचे दी गई है। इसके अलावा, जिस कीमत पर इन उत्पादों के प्रकारों का जांच की अवधि के दौरान चीन से आयात किया जा रहा है, उसका नीचे उल्लेख किया गया है। यह देखा जाएगा कि जिस कीमत पर याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों से उत्पाद का आयात किया है, वह चीन के उत्पादकों द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद की कीमत से काफी अधिक है।

क्रम सं.	उत्पाद प्रकार	औन्स द्वारा आयात			औन्स	चीन से आयात		
		मात्रा (एमटी)	कीमत (रुपए)	मूल्य (रु./एमटी)		मात्रा (एमटी)	कीमत (रुपए)	मूल्य (रु./एमटी)
1	एआर/रोविंग	***	***	***	***	***	***	***
2	सीएसएम	***	***	***	***	***	***	***
3	टी-30/डीआर	***	***	***	***	***	***	***
4	डीयूसीएस	शून्य	शून्य	शून्य	--	***	***	***
5	कुल	***	***	***		***	***	***

- याचिकाकर्ता ने इन उत्पादों का चीन से भी काफी अधिक कीमत पर आयात किया है अथवा याचिकाकर्ता की पुनः बिक्री की कीमत चीन से काफी अधिक है। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा आयात किया गया है और चूंकि याचिकाकर्ता निर्यातक से संबंधित है, इसलिए कानून के तहत इन उत्पादों की पुनः बिक्री की कीमत पर विचार किए जाने की जरूरत है।
- मैसर्स ऊर्जा प्रोडक्ट्स ने तथ्यात्मक रूप से गलत निदान दिया है। ई-ग्लास फाइबर और सी-ग्लास फाइबर, दोनों ही विचाराधीन उत्पाद के भाग के अलावा कुछ नहीं है। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच के समय और वर्तमान जांच में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उसके अपने प्रवेश से सी-ग्लास फाइबर काफी सस्ता है और यदि इन्हें आयात की अनुमति प्रदान की जाती है तो घरेलू उद्योग को क्षति का सामना करना होगा।
- जहां तक सेयरटैक्स इंडिया का संबंध है। सेयरटैक्स ग्लास फैब्रिक का एक उत्पादक है। याचिकाकर्ता ने ग्लास फैब्रिक को मूल जांच के समय विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया था। याचिकाकर्ता किसी भी तरह से किसी समीक्षा याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ा नहीं सकता। इसके अलावा, ग्लास फैब्रिक के निर्माण में मूल्य वर्धन 35% से अधिक है और इसीलिए ग्लास फैब्रिक का आयात पाटनरोधी शुल्क का निवारण नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने ग्लास फैब्रिक के लिए नई पाटन याचिका दाखिल करने की संभावना का पता लगाया है। तथापि, केवल याचिकाकर्ता का ही उत्पादन भारतीय उत्पादन से 50% से कम है और इसीलिए याचिकाकर्ता अन्य घरेलू

उत्पादकों के सहयोग के बिना याचिका दाखिल नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता को अन्य उत्पादकों के साथ मिलकर याचिका दाखिल करने की संभावना तलाशनी होगी। किसी भी मामले में केवल इस कारण से कि ग्लास फैब्रिक का देश में पाटित मूल्यों पर आयात हो रहा है, यह अर्थ नहीं हो सकता कि प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद को बाहर करे। वास्तव में शुल्क के दायरे से इस उत्पाद के प्रकार के बाहर करने का तात्पर्य केवल घरेलू उद्योग याचिकाकर्ता को ही क्षति होना नहीं है बल्कि ग्लास फैब्रिक के उत्पादकों को भी है। किसी भी तरह से ग्लास फैब्रिक को क्षति होनी जारी रहेगी क्योंकि चीन के उत्पादकों द्वारा किसी भी तरह से उत्पाद का पाटन करने की संभावना है।

प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

38. इस संबंध में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के विचार इस प्रकार हैं:

- i. आयातकों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान निरंतर अपने वैश्विक सहयोगियों से विचाराधीन उत्पाद का आयात करता रहा है और अप्रैल-अक्तूबर, 2015 की अवधि में भी ऐसा करना जारी रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा किया गया आयात छोटी मात्रा में नहीं है बल्कि काफी बड़ी मात्रा में और भारत में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों से कम कीमतों पर किया गया है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संयुक्त राज्य से 0.84 यूएस डॉलर प्रति किग्रा. की दर से करीब 1405 मी.टन. प्रत्यक्ष रोविंग का आयात किया है। इसी अवधि में चीन से आयात, जिस पर करीब 20% की दर से पाटनरोधी शुल्क लगाया था, उपभोक्ता द्वारा करीब 1.03 यूएस डॉलर प्रति किग्रा. की लागत पर आयात किया जा रहा था। घरेलू उद्योग अपने उपभोक्ताओं को आयातित वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है क्योंकि उनका अपना उत्पादन पर्याप्त नहीं है।
- ii. मैसर्स ऊर्जा प्रोडक्ट्स प्रा. लि., जो ग्लास फैब्रिक का एक निर्माता है, ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग केवल कोर्स टैक्स के ग्लास फाइबर का निर्माण कर रहा है और फाइबर टैक्स अथवा फाइबर ग्रेड को उपभोक्ताओं को शुल्क लगाने का नुकासन है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि दो प्रकार के कॉन्फिगुरेशन हैं अर्थात् इलैक्ट्रिकल ग्रेड ग्लास फिलामेंट के लिए ई-ग्लास फाइबर तथा कैमिकल रेजिस्टेंट ग्लास यार्न के लिए सी-ग्लास फाइबर। घरेलू उद्योग ई-ग्लास से केवल रोविंग का निर्माण कर रहा है और उन आयातकों को सी-ग्लास रोविंग के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए जो बिना पाटनरोधी शुल्क के काफी सस्ता है। शुल्क लगाए जाने से निचले उद्योग प्रभावित होंगे जिससे कि चीन के आयात अधिक महंगे हो रहे हैं।
- iii. मैसर्स सेयरटैक्स इंडिया प्रा. लि. ग्लास फाइबर फैब्रिक का विनिर्माता है, जिसने ग्लास फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का इस आदार पर विरोध किया है कि कि ग्लास फैब्रिक पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से ग्लास फैब्रिक के निर्माण के लिए कच्चा माल महंगा हो जाएगा जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि ग्लास फैब्रिक के आयातों में तेजी आएगी और ग्लास फैब्रिक के सभी निर्माताओं को फैब्रिक के सस्ते आयातों का सामना करना होगा। अतः उन्होंने ग्लास रोविंग से शुल्क हटाने के लिए अनुरोध किया है, जो कि ग्लास फैब्रिक के लिए एक कच्चा माल है अथवा ग्लास फैब्रिक पर भी शुल्क लगाया जाए जो कि उनका परिष्कृत सामान है और विंड मिल ब्लेड के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विशिष्ट अनुरोध और जो संगत समझे गए हैं, उन्हें प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से समझा गया है:

- i. तीसरे देशों से याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा किए गए आयातों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये आयात ऐसे देशों से हैं जो जांच के अधीन नहीं हैं। ये आयात आयातक के वैश्विक संबद्ध उत्पादकों द्वारा किए गए हैं और इसीलिए नियमों के तहत प्राधिकारी को उत्पादों की पुनः बिक्री की कीमत पर घरेलू कीमतों पर इन आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए विचार करने की जरूरत है। इसके अलावा, नियम 2(ख) के तहत केवल संबद्ध देशों से उत्पादों के आयात पर विचार किए जाने की जरूरत है। तीसरे देशों से आयात, घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता की पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजन से संगत नहीं है। चूंकि इन देशों से आयात एक ऐसी कंपनी द्वारा किए गए हैं, जो निर्यातक से संबंधित है, इसलिए प्राधिकारी को ऐसे उत्पादों की पुनः बिक्री की कीमत पर विचार करने की जरूरत है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि इन उत्पादकों की पुनः बिक्री की कीमत खरीद कीमत से काफी अधिक है।

- ii. जहां तक ई-ग्लास फाइबर और सी-ग्लास फाइबर का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही विचाराधीन उत्पाद का भाग है और इसीलिए इन उत्पाद प्रकारों को बाहर करने का मामला नहीं बन सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भी बाजार में ग्लास रोविंग की बिक्री कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद की चार अलग किस्मों अर्थात् प्रत्यक्ष रोविंग, संकलित रोविंग, चोर स्ट्रैंड और चोप स्ट्रैंड मैट के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच के दौरान अथवा वर्तमान समीक्षा जांच के दौरान ग्रेड-वार अथवा टैक्स-वार पहचाना नहीं गया है।
- iii. जहां तक ग्लास फैब्रिक के आयातों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ग्लास फैब्रिक वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है। यदि ग्लास फैब्रिक का चीन के उत्पादकों द्वारा पाटन किया जा रहा है तो यह वर्तमान जांच के दायरे के भीतर नहीं आ सकता। प्रभावित घरेलू उद्योग को नियम 5 अथवा नियम 25 के तहत राहत की मांग करनी चाहिए। पाटनरोधी शुल्क का औचित्य घरेलू उद्योग और विदेशी निर्यातक दोनों के लिए एक समान वातावरण तैयार करना है। यदि निचले उद्योग/आयातक/उपभोक्ता यह चाहते हैं कि उनके परिष्कृत माल पर शुल्क होना चाहिए तो इसकी अलग से जांच की जानी चाहिए और इसमें अलग से आवेदन दाखिल करने की जरूरत है जिसकी गुण-अवगुण आधार पर जांच की जाएगी।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

40. घरेलू उद्योग ने अन्य के साथ-साथ यह अनुरोध है कि:

- i. चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी भी देश ने चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा कोई भी निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए योग्य बनने हेतु प्रत्येक शर्त को पूरा नहीं करता। इस प्रकार चीन के उत्पादक की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।
- ii. भारत चीन के लिए प्रतिनिधि देश है, जिसके परिणामस्वरूप सटीक और पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा, अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी भारत को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश माना गया है।
- iii. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिक्री कीमत एक हानि वाली कीमत है, भारत में उत्पादन की लागत को समायोजन करके तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।
- iv. याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत की गणना करने के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान किए गए सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- v. विभिन्न उत्पाद प्रकारों की लागत और कीमत में पर्याप्त अंतर को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए अलग निर्यात कीमत निर्धारित की है।
- vi. उच्च सागर पार बिक्री सौदों के मामले में, प्राधिकारी को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत पर विचार नहीं करना चाहिए। वास्तव में यह मान लेना चाहिए कि प्रश्नावली उत्तर इन मामलों में पूरे नहीं है।
- vii. यूरोपीय यूनियन और सीएसए ने अनेक मामलों में भारत को किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में माना है। इसी की आपत्तियों और निर्धारणों को केवल इस कारण से अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि उनके द्वारा निर्धारित मार्जिन भारत द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक है। यद्यपि चीन से यूरोप के लिए उत्पाद की निर्यात कीमत भारत से अधिक है लेकिन भारत में पाटन मार्जिन यूरोप द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन की तुलना में कम है।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने निर्धारित प्रारूप के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को खपत, परिवर्तन लागत और अन्य संगत कीमत संबंधी आंकड़ों की विस्तृत सूचना प्रदान की है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

41. निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक की निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन किया जाए क्योंकि उसने वर्तमान जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार निर्यात कीमत निर्यातक द्वारा रखे गए आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए।
- ii. चीन के लिए सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 की अपेक्षाओं के अनुरूप है। शेनयांग मुत्सुशिता एस. बैट्री कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. और अन्य में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमतों का अंतिम उपाय के रूप में ही सहारा लिया जाना चाहिए। भारत को चीन के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए एक "उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश" के रूप में विचार नहीं किया जा सकता।
- iii. भारत को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गणना गलत होगी और चीन जन गण से निर्यातक भारत और चीन जन गण में कार्य कर रही पूरी तरह से अलग-अलग संस्थाएं हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि दोनों के बीच विभिन्न कार्यात्मक भिन्नताएं हैं।
- iv. भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमतों का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब अन्य दो विकल्प समाप्त हो चुके हों, जिसके लिए याचिकाकर्ता विफल हो गया है।
- v. याचिकाकर्ता कीमत संबंधी गणना के लिए एक सदृश देश का प्रस्ताव करने में विफल रहा है और यह उपरोक्त कानूनी बिन्दु का सीधा उल्लंघन है। संयुक्त राज्य से उत्पाद के आयात को ऐसे सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए भी यदि कानून में अनुमत हो तो उपयोग किया जा सकता है।
- vi. उच्च सागर पार बिक्री के संबंध में निर्यात के आंकड़ों में प्रदान की गई कीमत की बजाए अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- vii. जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।
- viii. याचिकाकर्ता उपयोग में लाई गई कच्चा सामग्री की कीमतों, खपत के मानकों, परिवर्तन लागतों, तथा निर्धारित सामान्य मूल्य के लिए लाभ के संबंध में ब्यौरे प्रदान करने में विफल रहा।

छ. चीन जन गण में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) दावों और सामान्य मूल्य के निर्धारण की जांच

42. जांच प्रारंभ करने की अवस्था में प्राधिकारी ने इस धारणा के अनुसार कार्रवाई की कि चीन जन गण एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। जांच आरंभ करने पर प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच आरंभ करने की सूचना का उत्तर देने तथा उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया। प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंड के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन सरकार से संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया है। निम्नलिखित निर्यातकों से प्रश्नावली उत्तर प्राप्त हुए हैं:

- क. जूशी ग्रुप कं. लि., तोंगजियांग
- ख. जूशी ग्रुप जियुजियांग कं. लि.
- ग. जूशी ग्रुप चेंगडु कं. लि.
- घ. चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन (सीपीआईसी)

ड. तैशान फाइबर ग्लास इंक.

43. तथापि, किसी भी निर्यातक ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दावे का खंडन करने का प्रयास नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछले वर्षों में चीन जन गण को भारत और अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।
44. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए और चीन की किसी भी निर्यात कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन न किए जाने पर प्राधिकारी चीन जन गण को वर्तमान जांच में एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन गण के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं।

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में यह प्रावधान है कि:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

45. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू बिक्री कीमतों अथवा एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से किसी अन्य देश को, जिसमें भारत भी शामिल है, निर्यात कीमत के आधार पर किया जाना है। तथापि, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण उपरोक्त विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर कर सकता है, जिसमें तर्क संगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित करके समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत शामिल है।
46. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि संयुक्त राज्य से उत्पाद के आयात को भी सामान्य मूल्य के निर्धारण में शामिल किया जा सकता है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि यूएसए से आयातों में केवल एक प्रकार का उत्पाद शामिल है। इस प्रकार से, किसी विश्वसनीय कीमत और किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए लागत व्यौरों के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित करके समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने प्रत्येक उत्पाद के प्रकार के लिए चीन में सभी निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है जिसका व्यौरा नीचे दिया गया है:

निर्यातक का नाम	निर्मित सामान्य कीमत
जूशी गुप कं. लि., तोंगजियांग	*** यूएस डॉलर/किग्रा
जूशी गुप जियुजियांग कं. लि.	*** यूएस डॉलर/किग्रा
जूशी गुप	*** यूएस डॉलर/किग्रा
चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन	*** यूएस डॉलर/किग्रा
तैशान फाइबर ग्लास इंक.	*** यूएस डॉलर/किग्रा
अन्य सभी निर्यातक/उत्पादक	*** यूएस डॉलर/किग्रा

निर्यात कीमत का निर्धारण

47. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जूथी ग्रुप जियुजियांग कं. लि., चीन जन गण द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक निर्यातक है। कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का दावा किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए गए आंकड़ों की अपनी फैक्ट्री में पुष्टि की है और प्राधिकारी द्वारा जूथी ग्रुप जियुजियांग कं. लि. के लिए निर्धारित किए गए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का ब्यौरा नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।
48. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जूथी ग्रुप झेजियांग कं. लि., चीन जन गण द्वारा प्रश्नावली उत्तर भी दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक निर्यातक है। कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का दावा किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दाखिल किए गए आंकड़ों की पुष्टि की गई थी और व्यक्ति पाटन मार्जिन, जो प्राधिकारी द्वारा जूथी ग्रुप झेजियांग कं. लि. के लिए निर्धारित किया जाना है, वह नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है।
49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जूथी ग्रुप चेंगडू कं. लि., चीन जन गण द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक उत्पादक है। कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का कोई निर्यात न होने का दावा किया है।
50. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली उत्तर मैसर्स जूथी (इंडिया) एफआरपी एसेसरीज प्रा. लि. द्वारा भी दाखिल किया गया है। आयातक जूथी ग्रुप निर्यातकों से संबद्ध है। उन्होंने अपने संबद्ध निर्यातक से आयातकों का दावा किया है और सभी सौदों का ब्यौरा दिया है। इसकी पुष्टि मुंबई में उनके कार्यालय में की गई थी। तथापि, वे केवल सीमित दस्तावेज ही प्रस्तुत कर सके, क्योंकि उनमें से कई उनके वेयरहाउस में लगी आग में नष्ट हो गए थे।

निर्यातक का नाम	निर्यातक मूल्य (यूएस डॉलर/किग्रा)
जूथी ग्रुप कं. लि., तोंगजियांग	***
जूथी ग्रुप जियुजियांग कं. लि.	***
जूथी ग्रुप	***

51. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रश्नावली उत्तर चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन, चीन जन गण द्वारा दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक निर्यातक है। कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातक का दावा किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दाखिल किए गए आंकड़ों की उनकी फैक्ट्री पर पुष्टि की गई है और प्राधिकारी द्वारा चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन के लिए निर्धारित किए जाने वाले व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का ब्यौरा नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है:

निर्यातक का नाम	निर्यात मूल्य (यूएस डॉलर/किग्रा)
चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन	यूएस डॉलर ***/किग्रा

52. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि तैशान फाइबर ग्लास इंक., चीन जन गण द्वारा प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि कंपनी विचाराधीन उत्पाद की एक निर्यातक है। कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात का दावा किया है। निर्यातक द्वारा अपने प्रश्नावली उत्तर में दाखिल आंकड़ों की मूल दस्तावेजों के साथ पुष्टि की गई और प्राधिकारी द्वारा तैशान फाइबर ग्लास इंक. के लिए निर्धारित किए जाने वाले व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन सारणी में दिया गया है:

निर्यातक का नाम	निर्यात मूल्य (यूएस डॉलर/किग्रा)
तैशान फाइबर ग्लास इंक.	यूएस डॉलर ***/किग्रा

चीन जन गण से असहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत

53. प्राधिकारी ने चीन जन गण से असहयोगी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है। तदनुसार, उचित समायोजन करने के बाद चीन जन गण से सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में कारखाना बाह्य स्तर पर भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नीचे सारणी में दिया गया है:

पाटन मार्जिन का निर्धारण

54. आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद, पाटन मार्जिन सारणी का आकलन नीचे सारणी में दिया गया है:

निर्यातक	सीएनवी	निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
यूनिट	(यूएस डॉलर/किग्रा)	(यूएस डॉलर/किग्रा)	(यूएस डॉलर/किग्रा)	(%)	(%)
जूशी ग्रुप कं. लि., तोंगजियांग	***	***	***	***	45-55
जूशी ग्रुप जियुजियांग कं. लि.	***	***	***	***	45-55
जूशी ग्रुप	***	***	***	***	45-55
चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन	***	***	***	***	40-50
टाइशन फाइबर ग्लास इंक.	***	***	***	***	50-60
असहयोगी निर्यातक	***	***	***	***	80-90

ज. क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

55. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया है:
- संबद्ध देश से पाटित आयात भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करना पाटनरोधी शुल्क के बावजूद पर्याप्त मात्रा में जारी रहा।
 - संबद्ध आयात घरेलू कीमतों से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटित आयातों की मात्रा में तेजी आएगी।
 - आयातों से जांच की अवधि में घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की अवस्था में बाजार में कीमत ह्रास का सामना करना होगा। इसके कारण लाभ में कमी आएगी और परिणामस्वरूप पूंजीगत और नकदी लाभ पर प्रतिफल में कमी आएगी।
 - याचिकाकर्ता ने उनके उत्पादों के लिए नए अनुप्रयोगों के विकास और उनके ग्राहक पोर्टफोलियो में वृद्धि करके नई प्रौद्योगिकी और उत्पाद अनुप्रयोगों में निचले निवेशों को प्रभावित किया है। पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग का विकास और नए उत्पादों व अनुप्रयोगों में निवेश के लिए इसकी क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
 - यदि शुल्क को हटा लिया जाता है और परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि होती है तो घरेलू उद्योग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित उत्पाद की कीमतों में पर्याप्त कमी लाने पर बाध्य होगा कि संबंधित उत्पाद एक कमोडिटी उत्पाद है।

- vi. यदि घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी करने पर बाध्य किया जाएगा तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर इसका वास्तविक प्रभाव पड़ेगा। लाभ में गिरावट से नकद प्रवाह और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट होगी।
- vii. यदि घरेलू उद्योग अपने सामान्य कीमत स्तरों का चयन करेंगे तो इससे इसकी बिक्री मात्रा की कम होने की संभावना है क्योंकि उपभोक्ता आयातों की ओर रुख करेंगे।
- viii. यदि घरेलू उद्योग बिक्री मात्रा की कमी को तरजीही देता है तो इससे काफी बड़ी क्षति होगी क्योंकि बिक्री की मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप इंटेंटी स्तर में वृद्धि, उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादन में कमी होगी।
- ix. याचिकाकर्ताओं ने निरंतर क्षति का दावा नहीं किया है, बल्कि इसकी बजाए पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर क्षति और पाटन के जारी रहने व पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

56. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति होने के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- i. क्षति अवधि के आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देश से आयातों में 33% की गिरावट हुई है। इसके अलावा, उत्पादन के संबंध में आयातों में 2011-12 में 39% से जांच की अवधि में 25% तक की गिरावट आई है। खपत की तुलना में आयातों की प्रवृत्ति में भी 2011-12 में 28% से जांच की अवधि में 19% तक की गहन गिरावट सामने आई है।
 - ii. घरेलू उद्योग के पास 61% घरेलू मांग है। आयातों में घरेलू मांग का केवल 19% शामिल है। संबद्ध देश से आयातों में याचिकाकर्ताओं के निष्पादन पर उतना प्रभाव पड़ता है जितना अन्य घरेलू उत्पादक, जिनके पास बाजार अंश का 12% है, समर्थ हैं।
 - iii. चीन के आयात मूल्यों में वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि में 27% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देश से आयातों में घरेलू मांग का 20% से भी कम शामिल है। अन्य देशों से आयात और अन्य घरेलू उत्पादकों से बिक्री को मिलकर घरेलू मांग का 24% होता है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों की कीमत संबद्ध देशों से आयातित कीमत से काफी कम है। अतः संबद्ध देश से आयातों के संबंध में कोई भी नकारात्मक कीमत प्रभाव नहीं है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2012-13 की अवधि में उपरोक्त मापदंडों के आधार पर निष्पादन में गिरावट आई है, जो मांग में कमी के कारण थी और वह वस्तुओं के प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने के कारण थी। तथापि, वर्ष 2012-13 और 2013-14 के बाद सभी निष्पादन संकेतकों में सुधार आया है।
 - v. याचिकाकर्ताओं का क्षमता उपयोग करीब 90% है, जो एक बढ़ते उद्योग के लिए एक मजबूत संकेतक है।
 - vi. घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के प्रचालनों के लिए लाभ में वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि में 40% तक की वृद्धि हुई है। नकद लाभों में 13% तक की वृद्धि और पीबीआईटी में 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि में 20-30% तक की वृद्धि हुई है। यहां तक कि आरओसीई की रेंज में भी वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि में 20-30% तक की वृद्धि हुई है। जिन कंपनियों के पास 20-30% तक का आरओसीई है, उन्हें ऐसी कंपनियां नहीं माना जा सकता जिन्हें कि क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है।
 - vii. इंटेंट्रियों में वर्ष 2011-12 की तुलना में जांच की अवधि में करीब 50% तक की गिरावट आई है। इसके अलावा, इंटेंटी स्तर में भी क्षति की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत स्थानों पर अपने अनुरोधों में विभिन्न तर्कों का सामना किया है।

58. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ... "ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा प्रयाप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"
59. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटन आयात के प्रभाव की जाँच के लिए, उपर्युक्त नियम के अनुबंध-II के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांक जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभ, निवल बिक्री, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार किया गया है।
60. वर्तमान जांच लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में भी यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसलिए, प्राधिकारी ने यथोचित परिवर्तनों सहित, अनुबंध II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति का निर्धारण किया है। इसके अलावा, चूंकि पाटन रोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू है, अतः प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करते समय सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयात पर मौजूदा पाटन रोधी शुल्क पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्राधिकारी ने जाँच की है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी उपाय, पाटन की समस्या, जिससे क्षति हो रही है, का सामना करने हेतु पर्याप्त है या नहीं है।
61. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 (ए) (5) के अनुसार, लगाया गया पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं कर दिया गया हो, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार, समीक्षा में, यह राय देती है कि इस तरह के शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनः शुरु होने की संभावना है, तो समय समय पर, इस तरह लगाए जाने की अवधि से पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके विस्तार के आदेश की तारीख से ही ऐसी अतिरिक्त अवधि की शुरुआत होगी।
62. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 (ए) (5) के अनुसार, लगाया गया पाटन रोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं कर दिया गया हो, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार, समीक्षा में, यह राय देती है कि इस तरह के शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनः शुरु होने की संभावना है, तो समय समय पर, इसे लगाए जाने की अवधि से पांच वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके विस्तार के आदेश की तारीख से ही ऐसी अतिरिक्त अवधि की शुरुआत होगी।
63. वर्तमान क्षति विश्लेषण के लिए, पाटन और क्षति के बीच क्षति तथा कारणात्मक संपर्क, यदि कोई है, की जाँच करने हेतु प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य प्रभाव तथा कीमत और लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जाँच की है

I. मांग का आकलन / स्पष्ट खपत

64. प्राधिकारी ने संबद्ध देश और अन्य देशों से आयात की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआई एंड एस से अधिप्राप्त लेनदेन-वार आयात आकड़ों पर विचार किया है। प्राधिकरण ने भारत में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत परिभाषित करने के लिए सभी स्रोतों से भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग पर विचार किया है। इस प्रकार आकलित मांग का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
घरेलू उद्योग की बिक्री	मे.ट	49,307	45,114	43,865	49,767
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	मे.ट	10,000	10,000	11,700	12,400
संबद्ध देशों से आयात	मे.ट	18,028	16,765	15,087	16,922
अन्य देशों से आयात	मे.ट	7,518	4,075	2,687	10,629
कुल मांग	मे.ट	84,853	75,954	73,339	89,718

65. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 और 2013-14 में मांग में गिरावट आई और उसके बाद पीओआई में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वर्ष 2012-14 में गिरावट का कारण, इस अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के सभी प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रों जैसे पवन ऊर्जा, पाइप/बुनियादी ढांचा उद्योगों, दूरसंचार उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योगों में मंदी का होना था।

II. पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा

आयात की मात्रा और बाजार हिस्सा

66. पाटित आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में संपूर्ण सामग्री के रूप में या उत्पादन अथवा खपत सापेक्ष पाटन आयात में व्यापक वृद्धि हुई है। पाटन रोधी नियम का अनुबंध II (ii) निम्नानुसार प्रावधान करता है:

“पाटित आयात की मात्रा की जांच करते हुए उल्लिखित प्राधिकरण इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या भारत में संपूर्ण सामग्री के रूप में या उत्पादन अथवा खपत सापेक्ष पाटन आयात में व्यापक वृद्धि हुई है।”

67. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यूओएम	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
आयात मात्रा					
चीन	मे.ट	18,028	16,765	15,087	16,922
अन्य देश	मे.ट	7,518	4,075	2,687	10,629
कुल	मे.ट	25,546	20,840	17,774	27,551
आयात में हिस्सेदारी					
चीन	%	71%	80%	85%	61%
अन्य देश	%	29%	20%	15%	39%
कुल	%	100%	100%	100%	100%
निम्न के संबंध में आयात					
उत्पादन(घरेलू उद्योग)	%	35%	32%	24%	37%
खपत	%	30%	27%	24%	31%
निम्न के संबंध में आयात					
भारत में उत्पादन	%	22%	22%	18%	19%
खपत	%	21%	22%	21%	19%

68. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात महत्वपूर्ण है, हालांकि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान उसमें गिरावट आई है। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में आयात महत्वपूर्ण बना हुआ है।

III. पाटित आयात के मूल्य और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

69. कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के संदर्भ में, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात के संबंध में घरेलू उद्योग के मूल्य पर प्रभाव की जाँच की गई है। इस विश्लेषण के लिए उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और घरेलू उद्योग के गैर क्षतिरहित कीमत(एनआईपी) की संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन आयात के पहुँच-मूल्य के साथ तुलना की गई है।
70. उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति का निर्धारण करने में, कर, रियायत, छूट और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए कमीशन को समायोजित किया गया है। कम कीमत पर बिक्री, क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है; इस प्रकार, प्राधिकरण ने एक क्षति रहित कीमत निकाली है और कम कीमत का पता लगाने के लिए पहुँच-मूल्य के साथ इसकी तुलना की है। जांच अवधि के दौरान विचाराधीन

उत्पाद के लिए उत्पादन की लागत पर उचित रूप से विचार करके इसकी निरंतर प्रवृत्तियों के अनुसार, घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन किया गया है। स्थिति इस प्रकार है:

i. कीमत कटौती

71. कीमत कटौती का निर्धारण उस अवधि के लिए संबद्ध देश के निर्यात मूल्य के साथ भारत में घरेलू बिक्री मूल्य की तुलना द्वारा किया गया है।

क्र. सं.	संबद्ध देश	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	आयात मात्रा	मे.ट	18,028	16,765	15,087	16,922
2	आयात का पहुँच मूल्य	रुपए/कि.ग्रा.	49	54	56	59
3	निवल बिक्री प्राप्ति	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
4	निवल बिक्री प्राप्ति	रुपए/कि.ग्रा. सूचित	100	103	113	123
5	कीमत कटौती	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
6	कीमत कटौती	रुपए/कि.ग्रा. सूचीबद्ध	100	83	111	132
7	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
8	कीमत कटौती की मात्रा	%	25-35	20-30	25-35	30-40

72. यहां पाया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में महत्वपूर्ण सकारात्मक कीमत-कटौती होने के बावजूद घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य आयात की पहुँच कीमत से कम है।

ii. कीमत अवमूल्यन/ह्रास

73. यह निर्धारित करने के क्रम में कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयात घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की कीमतों का अवमूल्यन अथवा मूल्य ह्रास कर रहे हैं, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए बिक्री की लागत और बिक्री राजस्व की प्रवृत्तियों पर विचार किया है। संबंधित जानकारी नीचे दी गई है-

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आयात का पहुँच मूल्य	रुपए/कि.ग्रा.	49.24	53.73	55.70	59.22
प्रवृत्ति	सूचक	100	109	113	120
बिक्री लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचक	100	116	118	141
बिक्री कीमत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचक	100	103	113	123

74. यह उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योग के बिक्री की लागत और बिक्री मूल्य दोनों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इस प्रकार, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का अवमूल्यन अथवा मूल्य ह्रास नहीं कर रहे हैं। हालांकि, बिना पाटनरोधी शुल्क के आयात की पहुँच कीमत, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत स्तर से भी कम है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू बाजार में काफी अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के कारण कम कीमत के आयात में वृद्धि होने की संभावना है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

75. कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने के उद्देश्य से आयात का पहुँच मूल्य और गैर क्षति रहित कीमत के बीच तुलना की गई। कम कीमत पर बिक्री अंतर निम्नानुसार है-

विवरण	इकाई	चीन जन.गण
क्षतिरहित कीमत	रुपए/मे.ट	***
पहुँच मूल्य (पीओआई)	रुपए/मे.ट	59.22
कम कीमत पर बिक्री	रुपए/मे.ट	***
कम कीमत पर बिक्री	%	*** %
कम कीमत पर बिक्री	% रेंज	30-40

76. उपरोक्त तालिका में यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को काफी कम कीमत का सामना करना पड़ा है।

IV. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मानकों की जाँच

77. पाटनरोधी नियम के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण के साथ समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटन आयात के अनुगामी प्रभाव की लक्षित जाँच को शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, नियम में प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटन के आयात पर प्रभाव की जाँच में सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों के लक्षित और निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ साथ बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, शेयर बाजार, उत्पादकता, निवेश पर लाभ या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नाकारात्मक प्रभाव, सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों को शामिल करे।

78. घरेलू उद्योग से संबंधित उपर्युक्त विभिन्न क्षति मापदंडों की जाँच निम्नानुसार की गई है:

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री

79. नीचे दी गई तालिका, क्षति-जाँच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग को दर्शाती है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जाँच अवधि
क्षमता	मे.ट	89,511	89,511	89,511	89,511
उत्पादन	मे.ट	73,241	64,862	72,699	75,369
कैप्टिव	मे.ट	5,293	5,890	8,078	8,156
क्षमता का उपयोग	%	82%	72%	81%	84%
घरेलू बिक्री	मे.ट	49,307	45,114	43,865	49,767

80. यह देखा गया है कि वर्ष 2013-14 में घरेलू उद्योग की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन उसके बाद वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में इन मानकों में गिरावट, मांग में गिरावट के कारण आई थी।

ख. मांग में बाजार-हिस्सा

81. घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर पाटन आयात के प्रभाव की निम्नानुसार जाँचा की गई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
संबद्ध देश	%	21.25	22.07	20.57	18.86
अन्य देश	%	8.86	5.37	3.66	11.85
घरेलू उद्योग	%	58.11	59.40	59.81	55.47
अन्य घरेलू उत्पादक	%	11.79	13.17	15.95	13.82
समग्र रूप से घरेलू उत्पादक	%	69.89	72.56	75.76	69.29

82. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू करने के साकारात्मक प्रभाव के रूप में संबद्ध देश की बाजार हिस्सेदारी में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ग. लाभ / हानि, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय

83. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जाँच लाभ / हानि, नकदी प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय के मामले की जांच निम्नानुसार की गई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	पीओआई
बिक्री लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	118	141
बिक्री कीमत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	113	123
प्रति इकाई लाभ/(हानि)	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	13	79	3
लाभ/(हानि)- कुल	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	12	70	3
नकदी लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	86	115
आरओसीई	%	***	***	***	***
आरओसीई	रेंज %	5-15	0-10	0-10	0-10

84. प्राधिकारी ने यह पाया है कि वर्ष 2012-13 में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में गिरावट आई और उसके बाद वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि में लाभ में वृद्धि का एक अंश, जैसा कि जांच अवधि में देखा गया है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन के मद्देनजर है, जिसके अनुसार लागत आवंटन में परिवर्तन हुआ है। बहरहाल, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में सुधार हुआ है।

घ. रोजगार और मजदूरी

85. रोजगार और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
रोजगार	नहीं	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	95	94
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	145	149
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता	कि.ग्रा..	282	250	294	309

86. चूंकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है, अतः रोजगार पाटन के प्रतिकूल प्रभाव का सूचक नहीं है। तथापि, यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है, जबकि मजदूरी भुगतान में वृद्धि हुई है।

ड सूची

87. घरेलू उद्योग के साथ सूची स्तर में गिरावट निम्नानुसार हुई है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
औसत स्टॉक	मे.ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूची	100	94	76	59

च. उत्पादकता

88. घरेलू उद्योग के प्रति दिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, जिसे नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
प्रतिदिन उत्पादकता	मे.ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	99	103
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मे.ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	104	109

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है, इसलिए घरेलू उद्योग पूंजी और निवेश बढ़ाने की स्थिति में है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि विनिर्माण इकाई (विचाराधीन उत्पाद) का एक महत्वपूर्ण भाग इसकी भट्टी है और इसका खास जीवन काल लगभग 10 वर्ष है। दोनों याचिकाकर्ताओं के संयंत्र में मौजूदा भट्टी का वर्ष 2016 के अंत में या वर्ष 2017 के शुरु में पुनर्निर्माण किया जाना है, जिसमें 250 करोड़ रुपये का निवेश और 30-35 के.टी. की अतिरिक्त क्षमता शामिल है। इस प्रकार, यदि पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ताओं की क्षमता को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो यह जोखिमपूर्ण होगा।

ज. वृद्धि

90. वर्ष 2012-13 में गिरावट के बाद उत्पादन, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, लाभ, निवेश पर लाभ और नकदी मुनाफे के मामले में घरेलू उद्योग में वृद्धि हुई है। हालांकि, पाटन कीमतों पर घरेलू बाजार में आयात लगातार जारी है और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कीमत कटौती हो रही है।

विवरण	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उत्पादन	%	-	-11%	12%	4%
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	-9%	-3%	13%
बिक्री लागत	%	-	16%	1%	20%
बिक्री मूल्य	%	-	3%	9%	9%
प्रति इकाई लाभ/हानि	%	-	-87%	516%	-97%

झ-पाटन का परिमाण

91. पाटन आयात घरेलू उद्योग को किस हद तक क्षति पहुँचा सकता है, के एक संकेतक के रूप में पाटन का परिमाण यह दिखाता है कि संबद्ध देश के खिलाफ निर्धारित पाटन न्यूनतम अंतर से ऊपर और सार्थक बना हुआ है।

ज. क्षति और क्षति मार्जिन का परिमाण

92. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारक मूल्य निर्धारित किया है। घरेलू उद्योगों का तर्क था कि प्राधिकरण को इस बात पर विचार करते हुए निवेश पर आय की अनुमति देनी चाहिए कि महत्वपूर्ण निवेशों का पहले ही मूल्य घट गया है और इसलिए या तो प्राधिकारी को इन निवेशों के बाजार मूल्य अथवा कम से कम आय की उच्च दर पर विचार करने के बाद निवेश पर आय की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि प्राधिकारी ने निवेश पर 22% आय की अनुमति देने की अपनी परंपरा का पालन किया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने हेतु घरेलू उद्योग के गैर क्षतिकारक कीमत की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। पीयूसी के विभिन्न प्रकारों अर्थात् प्रत्यक्ष रोविंग (Rovings), असेंबल रोविंग (Rovings), चॉण्ड स्ट्रेड्स और चॉण्ड स्ट्रेड्स मेट्स के लिए एनआईपी का निर्धारण किया गया है। निम्नानुसार क्षति मार्जिन निकाला गया है:

विवरण	गैर क्षतिकारक कीमत	पहुँच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन रेंज
इकाई	अमरिकी\$/कि.ग्रा.	अमरिकी\$/कि.ग्रा.	अमरिकी\$/कि.ग्रा.	%	%
जूशी ग्रुप क. लि. टोंगजियांग	***	***	***	***	15-25
जूशी ग्रुप जिजिउआंग क. लि.	***	***	***	***	20-30
जूशी ग्रुप	***	***	***	***	15-25
चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	15-25
टाइशान फाइबर ग्लास इंक.	***	***	***	***	20-30
गैर-सहकारी निर्यातकर्ता	***	***	***	***	40-50

ट. कारणात्मक संबंध

93. नियम, प्राधिकारी को पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को पाटन आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच करने का अधिकार देते हैं। निम्नलिखित समस्याओं को प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है और इनकी गैर-आरोपण विश्लेषण के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच की गई है:

- मांग में संकुचन:** क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मांग में संभावित गिरावट को घरेलू उद्योग के लिए क्षति के एक संभावित कारण के रूप में नहीं माना जा सकता।
- खपत पैटर्न:** - घरेलू उद्योग को प्रभावित करने की शर्तों को प्रभावित करते हुए संबद्ध वस्तु के लिए खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।
- प्रतियोगिता की शर्तें:-** प्राधिकारी ने पाया है कि जांच में यह नहीं देखा गया है कि घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति हेतु प्रतियोगिता की शर्तें या व्यापार प्रतिबंधी व्यवस्था जिम्मेदार हैं।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास:-** प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच में यह नहीं देखा गया है कि उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया या उपयोग में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।
- घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन:-** पीओआई के दौरान मामूली गिरावट के साथ क्षति जांच के समय घरेलू उद्योग के निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन को अलग-अलग और केवल अपने घरेलू प्रचालन के लिए विश्लेषित किया गया है।

ठ क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी निष्कर्ष

94. यह पाया गया है कि सभी आर्थिक मापदंडों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्सेदारी, लाभ, नकद मुनाफा और नियोजित पूंजी पर आय के मामले में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही है। इस प्रकार संबद्ध आयात के कारण पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक मानकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत अवमूल्यन और कीमत ह्रास के मामले में पाटन आयात के कारण बड़ी क्षति हुई है।

ड. पाटन और क्षति के जारी रहने तथा पुनरावृत्ति की संभावना

95. प्राधिकरण ने पाया कि यह एक सार (सनसेट) समीक्षा जांच है और इस जांच में ध्यान, क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच पर केन्द्रित है, यदि किसी तरह की वर्तमान क्षति न होने की सूरत में भी शुल्क को हटाया गया था। भले ही संबद्ध आयात में गिरावट आने के बावजूद भी, फिर भी अभी भी यह घरेलू बाजार में प्रवेश कर रहे हैं और इनका पाटन हो रहा है तथा इनकी क्षतिकारक कीमत है।

घरेलू उद्योग के विचार

96. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित दलील दी गई है:

- i. चीन 2010 से यूरोपीय आयोग द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को अपनी ओर खींच रहा है। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में एक अंतरिम समीक्षा कर चीन पर पाटनरोधी शुल्क में बढ़ोत्तरी की है और चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाया है। यह स्पष्ट रूप से संबद्ध देश द्वारा वस्तुओं के निर्यात में तीव्रता सूचित करता है।
- ii. आयातों में मूल जांच के आधार वर्ष से 316% की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि मांग में 136% तक बढ़ोत्तरी हुई है। अतः पाटनरोधी शुल्क के होने के बावजूद आयातों में मांग में हुई बढ़ोत्तरी से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है। यह संभावना है कि शुल्कों को रद्द कर देने से आयात में और वृद्धि होगी तथा आयातों से घरेलू उद्योग कम हो जाएंगे।
- iii. पूर्व जांचों में तथा वर्तमान याचिका में निर्धारित पाटन मार्जिन सकारात्मक और सार्थक है। यह पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति की संभावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पूर्व जांच में सहयोगी और असहयोगी दोनों तरह से निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने 25% से 60% तक पाटन मार्जिन प्रदान किया। वर्तमान जांच में सभी उत्पादों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन 16% है।

उत्पादक	क्षमता (000 एमटी)
जूशी ग्रुप कं. लि.	1,000
चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन	448
तैशान फाइबर ग्लास इंक. एंड तैशान फाइबर ग्लास (जोउचेंग) कं. लि.	425
वीबो	170
शांडोंग फाइबर ग्लास कम्पोजिट मेटेरियल्स कं. लि.	180
जियांग्सू चंघाई कम्पोजिट मेटेरियल्स कं. लि.	100
चांगझोउ तियामा ग्रुप कं. लि.	30
पीपीजी सिनोमा जिंगजिंग फाइबर ग्लास कं. लि.	60
जिंगताई जिननियु फाइबर ग्लास कं. लि.	60
जियांग्सू जियुडिंग न्यू मेटेरियल कं. लि.	70
कुल	2543

- iv. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक व्यापक क्षमताएं बना कर रखते हैं। घरेलू उद्योग ने इन देशों में अधिशेष क्षमताओं के तथ्य को दर्शाने के लिए चीन में कुछ उत्पादकों की अनुमानित क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई है जिससे वे शुल्क रद्द होने की स्थिति में वस्तुओं का पाटन करने में सक्षम हो सकें। संबद्ध देश से उत्पादकों के पास उत्पाद क्षमताओं को दर्शाने वाली प्रासंगिक सूचना नीचे दी गई सारणी में दर्शाई गई है।

- v. याचिकाकर्ताओं ने भी सतत् फिलामेंट ग्लास फाइबर उत्पादों पर समान शुल्क लगाने के लिए अपने आवेदन-पत्र में यूरोपियन ग्लास फाइबर प्रोज़्यूसर्स एसोसिएशन के द्वारा भेजी गई ग्लोबल और चाइना ग्लास फाइबर इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012-15 पर भरोसा किया। चीन के उत्पादकों की क्षमता 4 मिलियन एमटी से अधिक बढ़ी है और वर्ष 2012 में चीन की खपत लगभग 18,74,000 एमटी थी। यह चीन के उत्पादकों के उत्पादन स्तर से काफी कम है।
- vi. याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया कि संबद्ध वस्तुओं का तीसरे देशों के लिए जिस मूल्य पर निर्यात किया जा रहा है, ऐसी औसत कीमतें चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए निर्यात मूल्य से काफी कम हैं। अतः यह दर्शाता है कि चीन काफी कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करने में सक्षम है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से भारतीय बाजार अधिक लाभप्रद बन जाएगा तथा उत्पादक अधिक तीव्रता से ऐसी कीमतों पर निर्यात करना शुरू कर देंगे जिससे घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी।

वर्ष	भारत		विश्व को	
	मात्रा (एमटी)	यूएसडी/किग्रा	मात्रा (एमटी)	यूएसडी/किग्रा
2007	35,165	1.2	7,48,689	1.1
2008	43,277	1.3	8,57,711	1.3
2009	48,420	1.0	6,23,782	1.1
2010	57,505	1.1	8,11,707	1.1
2011	49,329	1.3	8,91,991	1.2
2012	42,934	1.3	9,27,016	1.2
2013	31,114	1.4	9,24,685	1.2
2014	37,806	1.3	9,29,138	1.2

- vii. जनता का अनुसंधान यह दर्शाता है कि चीन का उत्पादन 3 मिलियन एमटी के आस-पास था। कुल उपलब्ध क्षमता संबद्ध देश के उत्पादन स्तर से काफी अधिक होगी। ग्लास फाइबर उद्योग चीन में एक उत्साहित उद्योग है तथा ग्लास फाइबर के उत्पाद और आपूर्ति में और अधिक बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है, जैसा कि ई.सी. के निष्कर्षों से स्पष्ट है। जूशी की योजना अपना क्षमता को 1.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की है, जो वैश्विक उत्पादन के 25% के बराबर है तथा इसके 50% का निर्यात करने की योजना है। तैशान फाइबर ग्लास ने 80,000 एमटी प्रतिवर्ष उत्पादन करने में सक्षम एक ग्लास फाइबर भट्टी का प्रचालन करने के लिए अपनी योजना के बारे में वर्ष 2013 में घोषणा की थी।
- viii. याचिकाकर्ताओं ने चीन के सीमा शुल्क के अनुसार तीसरे देशों के लिए चीन से निर्यातों के बारे में विश्लेषण किया है। यह देखा गया है कि तीसरे देशों के लिए चीन के द्वारा किए गए 1,41,388 एमटी की मात्रा के निर्यात पाटित कीमतों पर है जो भारत की कुल मांग से अधिक है। इसके अलावा, भारत में उत्पादन, बिक्री और खपत के संबंध में चीन के द्वारा पाटित निर्यात काफी है।
- ix. आयातों के पहुँच मूल्यों की घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से तुलना काफी सस्ते मूल्य को दर्शाती है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क रद्द होने से यह स्पष्ट होता है कि निर्यातकर्ता भारतीय बाजार में अपने निर्यातों में और बढ़ोत्तरी करेंगे तथा उनकी व्यापक क्षमताओं को मानते हुए इससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

97. नीचे दिए गए कारकों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है:

- i. क्षति अवधि और पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयातों में पूर्णतः और उत्पादन तथा खपत के संदर्भ में धीरे-धीरे कमी आई है।
- ii. पीओआई तथा पीओआई के बाद की अवधि के दौरान पाटन नहीं हुआ है तथा किसी पाटन की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है।
- iii. ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में चीन में व्यापक अनुप्रयोग क्षमताएं हैं।
- iv. यूरोपियन आयोग द्वारा की गई जांचों के संदर्भ प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि शुल्क का निर्धारण वर्तमान जांच में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए।
- v. बिना किसी सूचना स्रोत के चीन में बड़ी क्षमताओं को बताते हुए एक अप्रमाणित सारणी में निर्यातकर्ताओं की क्षमता में किसी वृद्धि को साबित नहीं करती है। वास्तव में, 16 चाइनीज फाइबर ग्लास क्लिन्स ने कोल्ड रिपेयर अवधि में प्रवेश किया है और वर्तमान जांच में पिछली क्षमता को पीओआई से ठीक पहले समाप्त कर दिया गया था।
- vi. क्षमता की उपलब्धता ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए एक पर्याप्त आधार नहीं है कि पाटन के जारी रहने अथवा उत्तरवर्ती क्षति की कोई संभावना नहीं होगी।
- vii. बाद के पीओआई आंकड़ों का पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। बाद के पीओआई आंकड़ों का केवल उस स्थिति में ही विश्लेषण करना होगा, जब पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति न हुई हो।
- viii. अन्य प्राधिकारियों के निष्कर्षों से भारतीय प्राधिकारी प्रभावित नहीं होने चाहिए और यूरोपियन कमीशन के सिद्धांतों को और न ही अन्य को स्वीकार करने का एक चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।
- ix. वर्तमान और विगत पाटन मार्जिनों का स्तर अप्रासंगिक है क्योंकि वर्तमान जांच क्षति की जांच तथा एक नई अवधि के लिए पाटन के लिए होती है।
- x. ई.यू. के द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाने का निहितार्थ भारत में आयातों के बढ़ने से नहीं होता है और इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है तथा भारत में वह आयात मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से होता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

98. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी होने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों के दावे के बारे में जांच की है। निम्नलिखित विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्कों को रद्द कर देने की स्थिति में क्या घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की कोई संभावना है।

क. पाटनरोधी शुल्क के बावजूद सकारात्मक मार्जिन और क्षति मार्जिन

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों में यद्यपि गिरावट आई है, परन्तु पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक बना रहता है। अतः संबद्ध देश के उत्पादकों के द्वारा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग के लिए पाटन को बढ़ाने तथा क्षति पहुँचाने की संभावना है।

ख. अन्य देश के द्वारा पाटनरोधी उपाय

100. यह नोट किया है कि यूरोपियन कमीशन ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं पर उत्पादकों तथा निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क और समान शुल्क लगाए हैं तथा पाटनरोधी जांच एवं सब्सिडी-रोधी जांच शुरू की है। अंतिम समीक्षा के माध्यम से शुल्क बढ़ाया गया

है और समाप्त होने संबंधी समीक्षा फिलहाल की जा रही है। इसने स्पष्ट रूप से पाटित कीमतों पर निर्यात वस्तुओं के लिए संबद्ध देश में निर्यातकों के झुकाव को दर्शाया है।

ग. पूर्व एवं वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्व जांचों और वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन सार्थक है, जो पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन और उत्तरवर्ती क्षति को जारी रखने की संभावना को दर्शाता है।

घ. उत्पादकों की अधिशेष उत्पादन क्षमता

102. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है तथा विभिन्न दस्तावेज रिकार्ड हुए प्रस्तुत किए हैं जो चीन के उत्पादकों की उच्च निर्यात अभिमुखीकरण और इन उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्धता को दर्शाते हैं। रिकार्डों के अनुसार चीन के उत्पादकों में संबद्ध वस्तुओं के लिए अधिक उत्पादन क्षमताएं हैं जो भारत में घरेलू मांग से बहुत अधिक हैं। मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त हो जाने की स्थिति में भारत में उत्पाद के पाटन के होने की अत्यधिक संभावना है। घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि ग्लास फाइबर उद्योग एक उत्साहवर्धक उद्योग है तथा ग्लास फाइबर के उत्पादन और आपूर्ति में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

ङ. उपायों की अनुपस्थिति में कीमत कम होना

103. प्राधिकारी ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर सस्ते कीमत रखने संबंधी प्रभाव के बारे में तथा घरेलू उद्योग पर इसके उत्तरवर्ती प्रभाव के बारे में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के प्रभाव की जांच की है। यह नोट किया है कि पाटनरोधी शुल्क सहित और इसके बिना मूल्य में कटौती पीओआई में अधिक है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह स्पष्ट है कि आयातों की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी जिससे घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति होगी।

च. भारत में निर्यातों की कीमतें शेष विश्व की कीमतों से ऊंची हैं

104. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत कीमत संबंधी उन आंकड़ों पर विचार किया है जिस पर चीन सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार तीसरे देशों तथा भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। यह नोट किया है कि तीसरे देशों के लिए संबद्ध देश के द्वारा संबद्ध वस्तुओं का जिस औसत कीमत पर निर्यात किया जा रहा है जो भारत के लिए निर्यात कीमत से कम है और वह कीमत पाटित कीमत ही है। अतः यह नोट किया है कि तीसरे देशों के लिए निर्यात पाटित कीमत से काफी कम कीमत पर किया जाता है। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से भारतीय बाजार अधिक लाभप्रद बन जाएगा तथा उत्पादक अधिक तीव्रता से ऐसी कीमतों पर निर्यात करना शुरू कर देंगे जिससे घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी।

ज. कारणात्मक संबंध

105. अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत प्राधिकारी को द्वारा पाटन और क्षति की संभावना तथा शुल्कों को जारी रखने की जरूरत के बारे में जांच करनी होती है। जांच ने यह दर्शाया है कि आयात पाटित मूल्यों पर किए गए थे, घरेलू उद्योग को एक बार दोबारा क्षति हुई है तथा यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो वस्तुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या अन्य जाने-माने सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है अथवा उनसे क्षति होने की संभावना है।

क) तीसरे देशों से आयात तीसरे देशों से आयात की मात्रा या तो नगण्य है अथवा कीमतें अधिक हैं। तीसरे देश के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

ख) उत्पादन की मांग: विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में कोई कमी नहीं हुई है और इसलिए घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति मांग में संभव कमी की वजह से नहीं हो सकती है।

- ग) खपत के पैटर्न में बदलाव: विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खपत के पैटर्न में बदलाव होने से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
- घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार नियामक कार्य और उनके बीच प्रतिस्पर्धा: ऐसा कोई व्यापार नियामक कार्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- ङ) प्रौद्योगिकी में विकास: यह नोट किया जाता है कि उत्पाद का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई वास्तविक बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए प्रौद्योगिकी में विकास से क्षति होने का कोई संभव कारक प्रतीत नहीं होता है।
- च) घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन: घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है। तथापि, केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में ही क्षति विश्लेषण किया गया है।
- छ) निर्यात निष्पादन: घरेलू उद्योग ने घरेलू प्रचालनों की वजह से ही क्षति का दावा किया है। प्राधिकारी ने उपयुक्त स्थानों पर निर्यात निष्पादन का अलग-थलग किया है।

ट. प्रकट करने के बाद टिप्पणियां

घरेलू उद्योग के विचार

106. घरेलू उद्योग के द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

- i. यू.पी. टिबंगा को इस वजह से एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कंपनी ने आयातकर्ता की प्रश्नावली संबंधी प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। यह मैरीनो पानेल प्रोडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट के निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। यदि आयातकर्ता ने प्रश्नावली संबंधी प्रत्युत्तर ठीक समय पर दायर कर दिया होता तो इसे संभवतः एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जा सकता है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद के बारे में विनिर्दिष्ट के अलावा सीमा शुल्क वर्गीकरण के अंतर्गत सूचना दी गई है और इसके अलावा कुछ उत्पाद किस्में ऐसी हैं जो विचाराधीन उत्पाद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और कुछ उत्पाद किस्में ऐसी हैं जो विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर होती हैं। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के बारे में शुल्क सारणी में विनिर्दिष्ट करें जिनके द्वारा सीमा शुल्क वर्गीकरणों को ध्यान में रखे बगैर शुल्क आकर्षित करना चाहिए जिसके अंतर्गत आयातकर्ताओं के द्वारा वस्तुओं की स्वीकृति दी जा रही है। "विचाराधीन उत्पाद" से संबंधित पैराग्राफ में बताई गई लेकिन शुल्क सारणी में न बताई गई किसी बात के बारे में वित्त मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी करते समय ध्यान में रखे जाने की संभावना होती है। इसके अलावा, पत्तन पर तैनात सीमा शुल्क प्राधिकारी वित्त मंत्रालय को द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं पर विचार करते हैं तथा उन पर भरोसा करते हैं।
- iii. याचिकाकर्ता ने चीन से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों से ग्लास फाइबर का आयात किया है।
- iv. ई-ग्लास फाइबर और सी-ग्लास फाइबर दोनों कुछ नहीं हैं अपितु विचाराधीन उत्पाद के हिस्से हैं। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांचों के समय पर तथा वर्तमान जांच में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्वयं आयातकर्ताओं के आने से, जब ग्लास फाइबर काफी सस्ता हो और यदि इनको आयात किए जाने की अनुमति हो, तो घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- v. याचिकाकर्ता ने मूल जांच के समय पर विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्लास फाइबर को शामिल नहीं किया था। वर्तमान मामले की अंतिम रूप से समीक्षा कर लिए जाने की वजह से याचिकाकर्ता किसी भी हालत में किसी भी समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र को बढ़ा नहीं सकता है। किसी मामले में, केवल इस कारण से

ग्लास फैब्रिक का पाटित कीमतों पर देश में आयात किया जा रहा है तो इसका निहितार्थ यह नहीं होता है कि प्राधिकारी के द्वारा घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद को छोड़ देना चाहिए।

- vi. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता के संदर्भ में सुधार हुआ है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पीओआई के दौरान पूर्णतः बढ़ोत्तरी हुई है तथा भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत के संदर्भ में पर्याप्त रहा है। आयातों में बढ़ोत्तरी मांग की बढ़ोत्तरी की अपेक्षा काफी अधिक है।
- vii. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती काफी सकारात्मक है। कीमत में कटौती, कम दाम पर बेचने, मूल्य का नियंत्रण करने एवं रोकने के संदर्भ में पाटित आयातों की वजह से काफी क्षति हुई है।
- viii. सेसटेट और निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा बारंबार यह कहा गया है कि यदि कीमत में कटौती, पाटन मार्जिन, क्षति सकारात्मक हो और आयातों की मात्रा वर्तमान की मात्रा के बराबर होने से अनिवार्य निष्कर्ष केवल यह होगा कि पाटनरोधी शुल्क हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- ix. याचिकाकर्ता भट्टी का पुनर्निर्माण करने के लिए *** करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश करने के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लगभग अंतिम चरण में हैं। इससे भारत में *** एमटी तक अपनी क्षमता का विस्तार होने की संभावना है। यह मानते हुए कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एनआईपी का निर्धारण करने के लिए ऐतिहासिक लागतों और निवेश पर लाभ के बारे में विचार किया है, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और एनआईपी में इस समय बढ़ोत्तरी होने की संभावना है, जब इन निवेशों को वाणिज्यीकरण कर दिया जाता है।
- x. ई.यू. चीन से आयातों के लिए विचाराधीन उत्पाद के बारे में फिलहाल अंतिम समीक्षा कर रहा है (वस्तुतः यूरोप में विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र भारत की अपेक्षा बड़ा है)।
- xi. पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इससे पाटन की संभावना भी सुनिश्चित होती है तथा घरेलू उद्योग को परिणामतः क्षति होगी।
- xii. जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं को तीसरे देशों के लिए निर्यात किया जा रहा है, उनकी औसत कीमतें भारत की निर्यात कीमत की अपेक्षा कम है। इसके अलावा, भारत के लिए निर्यात पाटित कीमतों पर है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की सीआईएफ कीमत को प्रतिशतता के रूप में (शुल्क के यथा मूल्य के रूप में) लगाया जा सकता है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

107. विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों (निर्यातक/आयातकर्ता/प्रयोक्ताओं) के द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:
 - i. कुल मांग याचिका की मांग से भिन्न होती है। प्राधिकारी के द्वारा रिकार्ड किए गए आंकड़ों तथा याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के बीच काफी अंतर होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि अंतिम समीक्षा जांच की शुरुआत दोषपूर्ण याचिका पर आधारित थी। जांच में प्राधिकारी द्वारा जिन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है, उन आंकड़ों में परिवर्तन करने के कारणों के बारे में प्रतिवादी को जानकारी नहीं है।
 - ii. याचिका में दिए मूल आंकड़ों के अनुसार, मांग का मूल्यांकन करते समय पीओआई के दौरान मांग में 1% की गिरावट हुई, जबकि पीओआई के दौरान चीन से आयात की मात्रा में 33% की गिरावट देखी गई है। संशोधित आंकड़ों के

अनुसार भी मांग में 6% की बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में पीओआई के दौरान चीन से आयातों में 6% की कमी आई है। इस प्रवृत्ति के दृष्टिगत चीन के विरुद्ध मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई मामला नहीं है।

- iii. घरेलू उद्योग केवल कोर्स टैक्स के ग्लास फाइबर का निर्माण कर रहा है और फाइबर टैक्स अथवा फाइबर ग्रेड को उपभोक्ताओं को शुल्क लगाने का नुकासन है। दो प्रकार के कॉन्फिगरेशन हैं अर्थात् इलैक्ट्रिकल ग्रेड ग्लास फिलामेंट के लिए ई-ग्लास फाइबर तथा कैमिकल रेजिस्टेंट ग्लास यार्न के लिए सी-ग्लास फाइबर। घरेलू उद्योग ई-ग्लास से केवल रोविंग का निर्माण कर रहा है और उन आयातकों को सी-ग्लास रोविंग के आयात की अनुमति दी जानी चाहिए जो बिना पाटनरोधी शुल्क के काफी सस्ता है। शुल्क लगाए जाने से निचले उद्योग प्रभावित होंगे जिससे कि चीन के आयात अधिक महंगे हो रहे हैं।
- iv. चीन से बाजार हिस्से में कमी हुई है, जबकि अन्य देशों से उनके हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है। चीन से आयातों में गिरावट देखी गई है, परन्तु मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। पीओआई के दौरान अन्य देशों से आयातों में भी 41% तक पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। घरेलू उद्योग के लिए मात्रा संबंधी कोई क्षति नहीं हुई है।
- v. चीन जन गण से कथित पाटन के बावजूद घरेलू उद्योग उस कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, जो प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक है। अतः सस्ती कीमत से बेचने से पर्याप्त क्षति हुई है, यह सच नहीं है।
- vi. प्राधिकारी के द्वारा नोट किए अनुसार, क्षति की अवधि में क्षति, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मांग में बाजार का हिस्सा, लाभ/हानि, नकद प्रवाह और आरओसीई, लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी हुई है।
- vii. इस तथ्य को मानते हुए कि घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से एनआईपी कम है, क्षति मार्जिन का निर्धारण अथवा सकारात्मक क्षति मार्जिन की उपस्थिति प्रासंगिक नहीं है।
- viii. कारणात्मक संपर्क के संबंध में प्राधिकारी ने निर्यातक के निम्नलिखित तथ्यों को अस्वीकार कर दिया:
 - क. चीन जन गण के अलावा देशों (मिस्र, मैक्सिको, अमेरिकी और थाइलैंड) से आयातों की मात्रा और कीमत से याचिकाकर्ताओं को क्षति हो सकती है। आयात की कीमतें, विशेषकर मिस्र और अमेरिकी की कीमतें लगभग उतनी हैं जितनी चीन जन गण से संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतें हैं।
 - ख. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी घट-बढ़ हुई थी। जांच की अवधि में मांग में सुधार होने के बावजूद चीन से आयातों में मामूली-सी बढ़ोत्तरी हुई थी।
 - ग. अपने निर्यात निष्पादन की वजह से याचिकाकर्ताओं की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट हुई है जो यह सुझाव देती है कि क्षति, यदि कोई हुई है, वह स्वतः होती है।
- ix. मौजूदा जांच के संबंध में यूरोपियन प्राधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई प्रासंगिक नहीं है। प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया है। यूरोपियन प्राधिकारियों के द्वारा वर्तमान समाप्त समीक्षा के बारे में कार्रवाई की जा रही है और यह पूरी तरह से संभव है कि पाटनरोधी शुल्क को ऐसी समीक्षा के बाद हटा दिया जाए।
- x. इस तथ्य को प्रकट करने के बारे में कोई प्रमाण नहीं है कि चीन के उत्पादकों के पास अधिक उत्पादन क्षमताएं हैं और ग्लास फाइबर उद्योग चीन में एक उत्साहवर्द्धक उद्योग है।

- xi. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत के लिए निर्यात शेष विश्व की तुलना में ऊँची कीमतों पर होता है। तथापि, स्रोत आंकड़ों को निर्यातक के द्वारा घनिष्ठ जांच हेतु पब्लिक फाइबर पर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, सीपीआईसी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जांच की अवधि और जांच की बाद की अवधि के छः महीनों, दोनों में, तीसरे देशों के लिए निर्यात भारत के निर्यातों की तुलना में अधिक कीमतों पर है।
- xii. बहिष्कार करने की शैली सभी किस्म के ग्लास वूवन रोविंग्स के लिए होती है और भविष्य में किसी प्रकार भ्रम होने से बचने के लिए तथा अदला-बदली को साफ-साफ लिखना होगा।
- xiii. क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने की पद्धति अस्पष्ट है जिसको माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा अपनाया गया है। कार्यकरण का ब्यौरा हितबद्ध पक्षकारों के साथ बांटा जा सकता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए लाभ की 22% दर गलती से मंजूर की है। घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने में शामिल किए जाने वाले लाभ की उचित दर हेतु अधिनियम में प्रावधान है। 2004(170).ई.एल.टी.144 (ट्रि-डेल) में सूचित इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेसटेट ने क्षतिरहित कीमत निकालने में अपनाए जाने वाले आरओसीई का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग की लाभ की ऐतिहासिक दर पर विचार करने के महत्व को उजागर किया।
- xiv. प्राधिकारी ने पीओआई में खपत के आधार पर कच्चे माल की लागत का गलती से निर्धारण किया है। प्राधिकारी ने “विगत तीन वर्षों की अवधि में तथा जांच की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग” पर विचार करने को अनिवार्य बनाया है।
- xv. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह नोट किया है कि नियमावली के तहत प्राधिकारी को घरेलू कीमतों पर इन आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादों की पुनः बिक्री कीमत पर विचार करना अपेक्षित है। तथापि, प्राधिकारी ने जिस आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला है कि ऐसी जांच करना आवश्यक है, उसके बारे में कानूनी प्रावधान संदेहास्पद है।
- xvi. स्वयं प्राधिकारी के निष्कर्षों के अनुसार, चीन जन गण से आयातों की मात्रा में पूर्णतः कमी हुई है। साथ ही, अन्य देशों से आयातों में बढ़ोत्तरी हुई है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 73 में यह स्वीकार किया है कि संबद्ध देश से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतें प्रतिबंधित अथवा कम नहीं हो रही हैं।
- xvii. घरेलू उद्योग के निष्पादन पर अन्य देशों से आयातों का प्रभाव पड़ा है, इस तथ्य को ध्यान में रखने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है। विशेषकर, वर्ष 2013-14 में शेयर 3.66% से बढ़कर पीओआई में 11.85% हो गया है। अन्य देशों से आयातों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।
- xviii. प्राधिकारी के द्वारा नोट किए अनुसार, क्षति की अवधि में क्षति, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, मांग में बाजार का हिस्सा, लाभ/हानि, नकद प्रवाह और आरओसीई, लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी हुई है।
- xix. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में:

क. अन्य देशों के द्वारा शुल्क लगाने से भारतीय प्राधिकारी के निर्णय प्रभावित नहीं होने चाहिए।

ख. पिछले चार वर्षों में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वस्तुतः स्वयं घरेलू उद्योग के द्वारा आयातों की वजह से मुख्यतः अन्य देशों से आयातों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

- ग. केवल अधिक क्षमताओं के होने से अधिशेष क्षमताएं बदलती नहीं हैं। विशेषकर, चीन की कंपनियां अधिक उपयोग करने के आंकड़ों के अनुसार कार्य कर रही हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह निष्कर्ष निकालने का कोई तर्क नहीं है कि यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो भारत के लिए आयातों में बढ़ोत्तरी होगी।
- घ. चीन तीसरे देशों के लिए निर्यात कर रहा है, इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि वह पाटन में लगा हुआ है। इसके अलावा, प्रतिवादी यह निवेदन करता है कि ओवेन्स कॉर्निंग भी चीन में एक संबद्ध कंपनी है जिसके द्वारा भी तीसरे देशों के लिए कथित पाटन किया जा रहा होगा।
- xx. प्राधिकारी के द्वारा कुछ मानदंडों के अनुसार अनुच्छेद 11.3 के तहत बाध्यताओं के अनुसार, "संभावित निर्धारण" करना चाहिए। विवेचन करते समय पीओआई के बाद के आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि मौजूदा मामले में इस अपेक्षा को पूरा किया जाता है क्योंकि कोई भी क्षति हुई पाई नहीं गई है तथा शुल्क में किसी प्रकार के विस्तार करने का औचित्य साबित करने के लिए प्राधिकारी के द्वारा उचित अनुमान लगाने चाहिए।
- xxi. अंतिम समीक्षा में प्राधिकारी के अधिकार शुल्क जारी रखने अथवा हटाने तक ही सीमित होते हैं और न कि इसका विस्तार करने के लिए। संबद्ध वस्तुओं का कोई पाटन नहीं होता है और संबद्ध वस्तुओं से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है, इस दावे के बारे में पूर्वाग्रह के बिना अंतिम समीक्षा का प्रयोजन यह जांच करना है कि क्या विचाराधीन उत्पाद के आयातों की वजह से पाटन और क्षति की संभावना के परिप्रेक्ष्य में पाटनरोधी शुल्क का जारी रखना उचित है।
- xxii. पाटनरोधी शुल्क का उस स्थिति में ही विस्तार किया जा सकता है यदि ऐसा कोई स्वीकारात्मक निष्कर्ष हो कि शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन और क्षति को जारी रखने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना होती है। एस.एस.आर. के द्वारा शुल्क को जारी रखना एक नियम की अपेक्षा एक अपवाद है।
- xxiii. डी.आई. से घरेलू मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए, संबद्ध देशों सहित अन्य देशों से आयात करना जरूरी हो जाता है। पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी, विशेषकर, मांग और आपूर्ति में अंतर होने की वजह से आयात लगभग उतना ही रहा है।
- xxiv. मै. टाइसन ने "अपशिष्ट" के रूप में जाने एक ऑफ ग्रेड उत्पाद का सीमित निर्यात किया जो उत्पादन प्रक्रिया की एक स्क्रेप होती है और सी.एस.एम. का "ऑफ-कट" होता है। अपशिष्ट का विक्रय मूल्य अन्य ग्रेडों से काफी कम होता है। भारत के लिए निर्यात किए गए अपशिष्ट की मात्रा पीओआई के दौरान टाइसन के द्वारा किए गए कुल निर्यातों के 2% से कम होती है। संबद्ध वस्तुओं की तुलना में भौतिक विशेषताओं और कीमत अत्यधिक अंतिम होने की वजह से विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से अपशिष्ट को निकाल देना चाहिए।
- xxv. यद्यपि टाइसन ने एम.ई.टी. स्तर के लिए दावा नहीं किया है, इसने बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों में कार्य किया है। टाइसन के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर सामान्य कीमत की गणना करने के लिए टाइसन ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है।
- xxvi. चूंकि, निर्यातों पर कोई उत्पादन बैट लागू नहीं होता है, इसलिए उत्पादन विदेशी क्रेताओं से उत्पादन बैट नहीं ले सकता है। तथापि, यह इस प्रकार भुगतान किए गए निवेश बैट पर बैट छूट का दावा कर सकता है। प्राधिकारी के द्वारा पाटन मार्जिन की गणना करने संबंधी प्रतिवादी के विवाद को ध्यान में रखना चाहिए।
- xxvii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में पूर्णतः वृद्धि हुई है, घरेलू बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री बढ़ी है तथा चीन से आयातों की मात्रा में कमी आई है। चीन से आयातों के बाजार हिस्से में जांच अवधि में आधार वर्ष से कमी आई है, जबकि अन्य देशों से आयातों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है।

- xxviii. चीन से आयातों की वजह से कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है। क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष यह निकाला है कि ए.डी.डी. के बिना आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के स्तर से भी कम है।
- xxix. चीन से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुँच मूल्य ने बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाई है। सस्ते दामों पर बेचने, यदि कोई है, के अन्य कारण हैं। प्रति यूनिट तथा कुल लाभ, आरओसीई, नकद लाभ, सभी सकारात्मक हैं। किसी भी आर्थिक मापदंड से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

प्राधिकारी के द्वारा जांच

108. सभी हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के द्वारा उठाए गए मुद्दों/वादों पर पहले पैराग्राफों में सविस्तार कार्रवाई की गई है। तथापि, स्पष्टता के लिए उनके बारे में निम्नलिखित पैराग्राफों में दुबारा समाधान किया जा रहा है:
- क. इस दावे का जहाँ तक संबंध है कि याचिका में उपलब्ध कराए गए आंकड़े और याचिकाकर्ताओं के द्वारा किए गए निवेदनों में दिए आंकड़े प्रकटन विवरण में दिए आंकड़ों से भिन्न हैं, इस बारे में प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि याचिका याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए गौण स्रोतों के आंकड़ों पर आधारित थी, जबकि प्राधिकारी ने जांचों की अवधि के दौरान बाद में प्राप्त किए गए डीजीसीआईएंडएस सौदे-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्रकटन विवरण में दी गई सूचना सत्यापित सूचना पर आधारित है, जबकि याचिका में दी गई सूचना याचिकाकर्ताओं के दावों पर आधारित थी। जांच करने का उद्देश्य सही तथ्यों की पुष्टि करना है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान मामला अंतिम समीक्षा करना है, इसलिए प्राधिकारी के द्वारा मूल जांच के यथा प्रतिकूल संभावना विश्लेषण करने के लिए आयातों की मात्रा के बारे में विचार करना अपेक्षित है, जबकि आयातों की मात्रा यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।
- ख. जहाँ तक ई-ग्लास फाइबर और सी-ग्लास फाइबर का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों ही विचाराधीन उत्पाद का भाग है और इसीलिए इन उत्पाद प्रकारों को बाहर करने का मामला नहीं बन सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भी बाजार में ग्लास रोविंग की बिक्री कर रहा है और विचाराधीन उत्पाद की चार अलग किस्मों अर्थात् प्रत्यक्ष रोविंग, संकलित रोविंग, चोर स्ट्रैंड और चोप स्ट्रैंड मैट के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच के दौरान अथवा वर्तमान समीक्षा जांच के दौरान ग्रेड-वार अथवा टैक्स-वार पहचाना नहीं गया है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग का जहाँ तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान उत्पाद की समग्र मांग बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अलावा, चीन से आयातों ने वर्ष 2013-14 तक गिरावट दर्शाई है, लेकिन पीओआई के दौरान इसमें बढ़ोत्तरी हुई। चूंकि, वर्तमान जांच एक अंतिम जांच हैं, इसलिए सभी मापदंडों पर घरेलू उद्योग को क्षति का होना घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण करने के लिए पूर्व-आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी के द्वारा यह निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है कि क्या घरेलू उद्योग को वास्तव में क्षति हुई है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की स्थिति में प्राधिकारी के द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। पीओआई के दौरान चीन से आयातों की मात्रा भारत में मांग/खपत का 18% है और इसलिए मात्रा स्वयं में ही काफी अधिक है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर देने की स्थिति में आयातों की तीव्रीकरण की संभावित स्थिति का सूचक है।
- घ. कुल आयातों में चीन के बाजार हिस्से में कमी आने का जहाँ तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान भारत में उत्पादन और खपत के संबंध आयातों का शेयर पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक था। अतः लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में चीन से आयातों की मात्रा काफी रही है।

- ड. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं को ऐसी कीमत पर बेच रहा है जो प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एनआईपी से अधिक है, यह बात सही नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एनआईपी से कम है। किसी मामले में केवल यह तथ्य, कि घरेलू उद्योग एनआईपी से अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री कर रहा है, घरेलू उद्योग को पाटन जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति की संभावना न होना अंतर्निहित नहीं होती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन से आयातों का पहुँच मूल्य उत्पादन की लागत, विक्रय मूल्य और घरेलू उद्योग के एनआईपी से कम हैं, इसका निहितार्थ यह है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में घरेलू उद्योग कीमत को कम करने के लिए बाध्य होगा और इस तरह घरेलू उद्योग की लाभप्रदता धीरे-धीरे प्रभावित होगी तथा घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियाँ होंगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एनआईपी की आयातों के पहुँच मूल्य से तुलना करने से कीमत में कमी देखी गई है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि सकारात्मक क्षति मार्जिन उस स्थिति में बहुत ही प्रासंगिक है जहां पर घरेलू उद्योग एनआईपी से अधिक कीमत पर पहले ही बेच रहा हो।
- च. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंडों ने सुधार दर्शाया है, इस दावे का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण में तथा वर्तमान निष्कर्षों में विश्लेषण में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि इन मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग विकृत हुआ है और न ही वर्तमान क्षति अवधि में इन मापदंडों में विकृति इस निर्णय के लिए पूर्व अपेक्षा है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति होगी। चूंकि, उत्पादन पाटनरोधी शुल्क आकर्षित कर रहा था, इसलिए इन आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार दर्शाया गया है। तथापि, यह देखना अपेक्षित है कि यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है, क्या घरेलू उद्योग का निष्पादन वर्तमान स्तरों पर ही रखा जाएगा अथवा घरेलू उद्योग का निष्पादन विकृत हो जाएगा। क्या वर्तमान शुल्क को हटा लेना चाहिए और यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बनाए रखता है, तो यह परिणाम निकलता है कि उपभोक्ताओं को जिस कीमत पर आज उत्पाद मिलते हैं, इससे सस्ती कीमत पर चीन के उत्पाद मिल जाएंगे। चीन में पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, इसलिए यह परिणाम निकलता है कि आयातकर्ता/उपभोक्ता चीन से बड़े आयातों का सहारा लेंगे। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ेगा और परिणामतः बाजार शेयर, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभों, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह में कमी का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक तौर पर, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने की स्थिति में, यदि घरेलू उद्योग, घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच के अंतर को कम करने के लिए कीमतों को कम करने का निर्णय लेते हों तो इसका परिणाम यह होगा कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता धीरे-धीरे विकृत हो जाएगी और घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियाँ होंगी। परिणामस्वरूप, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह भी विकृत हो जाएगा। निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह भी नकारात्मक हो जाएंगे। अतः पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग का निष्पादन मात्रा और कीमत दोनों की दृष्टि से विकृत हो जाएगा।
- छ. कारणात्मक संपर्क के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जहां तक मिस्र और अमेरिका से आयातों का संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका की आयात कीमत अधिकांशतः याचिकाकर्ता के द्वारा किए गए आयातों को दर्शाती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्या गैर-संबद्ध देशों से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, यहां पर यह प्रासंगिक बात है और इसलिए दोनों पक्षकारों के बीच में संबंध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य पर विचार किया है। अमेरिका से आयात कीमत और याचिकाकर्ताओं के विक्रय मूल्य के बारे में सविस्तार जांच की गई थी और यह देखा गया है कि याचिकाकर्ताओं का विक्रय मूल्य चीन के आयात मूल्य से अधिक है। यदि किसी मामले में तीसरे देशों से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें ठहर गई हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। यदि तीसरे देशों के आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें ठहर गई हैं तो इन आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।

- ज. उत्पाद की मांग के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि मांग में कुछ घट-बढ़ हुई थी, परन्तु भारत में उत्पाद की समग्र मांग सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके अलावा, चाहे भारतीय उद्योग पूर्ण क्षमताओं पर उत्पादन पर उत्पादन करे, पर भारतीय उद्योग देश में उत्पाद की केवल 69% मांग को ही पूरा करेगा। किसी मामले में शेष मांग को आयातों से ही पूरा करना होगा। अतः यह ऐसा मामला नहीं है जहां पर घरेलू उद्योग का उत्पादन मांग की घट-बढ़ अथवा मांग में कमी होने की वजह से ही प्रभावित होता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्राधिकारी का समनुरूप कार्य यह होता है कि देश में उत्पाद की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग को पर्याप्त क्षमताएं रखने की जरूरत नहीं होती है। देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए सामर्थ्य को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अथवा जारी रखने के लिए एक जरूरी पूर्व-अपेक्षा के रूप में देखा नहीं गया है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि वे पर्याप्त निवेश सहित पर्याप्त क्षमता में उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए भट्टी पुनः बना रहे हैं।
- झ. याचिकाकर्ताओं के निष्पादन की वजह से उनकी लाभप्रदता में तेजी से कमी आने का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी ने केवल घरेलू प्रचालनों (कार्यों) के लिए ही घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, लाभों, निवेश पर लाभ और नकद प्रवाह के बारे में विचार किया है। इसलिए घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करते समय किसी मामले में निर्यात निष्पादन की संभव विकृति के बारे में विचार नहीं किया गया है। वर्तमान निर्धारण घरेलू उद्योग की क्षति की संभावना पर आधारित है। जांच ने यह दर्शाया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने केवल संभव अथवा कपटपूर्ण स्थिति पर अपना निर्धारण नहीं किया है। प्राधिकारी की निर्धारण जांच और सत्यापित तथ्यों पर आधारित है। घरेलू उद्योग की सत्यापित सूचना यह दर्शाती है कि आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य, उत्पादन की लागत और एनआईपी से काफी कम है। अतएव, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से कीमत में काफी कटौती हो जाएगी और कीमत सस्ती हो जाएगी। उत्पादन की लागत, विक्रय मूल्य, प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एनआईपी और आयातों के पहुँच मूल्य से संबंधित सकारात्मक प्रमाण के आधार पर प्राधिकारी के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। घरेलू उद्योग ने इस बात का प्रमाण देते हुए वित्तीय आंकड़े उपलब्ध कराए कि आयातों का पहुँच मूल्य उत्पादन की लागत, विक्रय मूल्य और प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एनआईपी से कम रहे हैं। अतः निर्धारण तथ्यों पर आधारित है और न केवल आरोप निराधार कल्पना और सुधार की संभावना पर।
- ञ. यूरोप में लागू पाटनरोधी शुल्क और यूरोप के द्वारा शुरूआत की गई अंतिम समीक्षाओं का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगा रहने, यूरोप में राजसहायतारोधी शुल्क और चीन के विरुद्ध पाटनरोधी और राजसहायतारोधी जांच की वर्तमान शुरूआत के तथ्य यह दर्शाते हैं कि उत्पाद का यूरोपियन बाजार में पाटन किया जा रहा था। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूरोपियन कमीशन द्वारा शुरूआत करने का नोटिस यह बताता है कि गणना किया गया पाटन मार्जिन संबंधित देश के लिए पर्याप्त है। कमीशन ने यह भी पाया है कि "यूनियन के लिए संबंधित देश से समीक्षाधीन उत्पाद के वर्तमान आयात स्तर में संबंधित देश में निर्यात करने वाले उत्पादकों की निर्माण सुविधाओं की अप्रयुक्त क्षमता के अस्तित्व की वजह से और समीक्षाधीन उत्पाद के लिए बढ़ती हुई मांग और अधिक कीमतों से यथा स्पष्ट ई.यू. बाजार की प्रत्यक्ष आकर्षण की वजह से बढ़ने की संभावना है।"
- ट. चीन में अधिशेष उत्पादन क्षमताओं के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जनता के प्रभाव क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त विवरणों के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने यह दर्शाते हुए सूचना प्रस्तुत की कि चीन के उत्पादकों में 25,43,000 एमटी तक क्षमताएं हैं और चीन के उत्पादक तीसरे देशों के लिए 9,29,138 एमटी तक उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने प्रतिकूल प्रमाण उपलब्ध करा करके याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के दावे को नामंजूर नहीं किया है। तीसरे देशों के लिए निर्यात करने के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों पर आधारित है तथा इसको भी नामंजूर नहीं किया गया है। इसके अलावा, ई.सी. के द्वारा जारी किया गया शुरूआत करने संबंधी नोटिस भी यह बताता है कि यूनियन के लिए चीन से समीक्षाधीन उत्पाद के आयात स्तर में संबंधित देश में निर्यात करने वाले उत्पादकों की निर्माण सुविधाओं की अप्रयुक्त क्षमता के अस्तित्व की वजह से बढ़ने की संभावना है जो ई.सी. के समक्ष यूरोपियन घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका पर आधारित है।
- ठ. तीसरे देशों के लिए चीन से निर्यात कीमत के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत और तीसरे देशों के लिए चीन से निर्यात कीमत की तुलना चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों पर आधारित है और उक्त सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संभावना जांच किसी विशेष निर्यातक तक ही सीमित नहीं हो सकती है और यह विभिन्न उत्पादकों के द्वारा विभिन्न वैश्विक बाजारों तक चीन से निर्यातों के संबंध में की जानी अपेक्षित है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी निर्यातक ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उनके निर्यातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

- ड. एनआईपी के निर्धारण का जहां तक संबंध है, इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआईपी का निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा समुरूप लागू की गई पद्धति के आधार पर किया गया है। नियोजित पूंजी का परिसंपत्तियों का लेखा कीमत के आधार पर निर्धारण किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए नियोजित पूंजी पर 22% लाभ प्रदान करने के लिए प्राधिकारी का यह समनुरूप कार्य है। वस्तुतः घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि उद्योग की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को समझते हुए प्राधिकारी के द्वारा अधिक लाभ स्वीकृत करना चाहिए कि घरेलू उद्योग की वर्तमान भट्टी को बदला जाना है जिसके लिए घरेलू उद्योग की भारी निवेश लागत होगी और इसलिए आरओआई के द्वारा इस निवेश को दर्शाना चाहिए। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की मांग के अनुसार, लाभ की उच्चतर दर के बारे में विचार नहीं किया है। साथ ही, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में लाभ की कम दर प्रदान करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि एनआईपी का फैक्ट्री के बाहर स्तर पर निर्धारण किया गया है।
- ढ. बाहर रखे गए उत्पादों को समुचित रूप से लेखाबद्ध करने का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी जूशी के दावे से सहमत है और उसने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में उचित संशोधन किया है।
- ण. यह स्पष्ट किया जाता है कि कच्चा माल लागत खपत संबंधी कारकों के बारे में नियमों के अनुबंध-III के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों की अवधि तथा जांच दरों की अवधि में घरेलू उद्योग के द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम समुपयोग पर विचार किया है।
- त. चीन से आयात की मात्रा में कमी आई है और तीसरे देशों से आयातों में बढोत्तरी हुई है, इस दावे का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन से आयातों की मात्रा में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक कुछ गिरावट दर्शाई है। तथापि, चीन से आयातों में वर्तमान पीओआई के दौरान बढोत्तरी हुई। साथ ही, पीओआई में अन्य देशों से आयातों में बढोत्तरी हुई है। तथापि, ये तीसरे देश याचिकाकर्ता से अधिकांश तौर पर संबद्ध हैं जिसकी सविस्तर जांच की गई है और यह पाया गया है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इन तीसरे देशों के आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- थ. कीमत को रोकने, नियंत्रित न करने के दावे का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान स्थिति को इस तथ्य के साथ-साथ देखने की जरूरत है कि पाटनरोधी शुल्क लागू है। जब पाटनरोधी शुल्क लागू होता है तब कीमत को रोकने और नियंत्रित न करने का निहितार्थ यह नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है, तब कीमत रोकने अथवा नियंत्रित करने की संभावना नहीं होती है। वास्तव में, पाटनरोधी शुल्कों के लागू होने की वजह से घरेलू उद्योग पर आयात को रोकने और नियंत्रण करने संबंध प्रभाव नहीं हुआ है।
- द. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि चीन में बड़ी-बड़ी क्षमताओं की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है तथा इससे अधिशेष क्षमताएं नहीं होती हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि चीन की कंपनियां अधिक प्रयुक्त दरों पर कार्य कर रही हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकार्डों में दी गई सूचना चीन के उत्पादकों की पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमताओं को दर्शाती हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने तीसरे देशों के लिए अपने निर्यात के प्रविष्टि-वार ब्यौरे के बिल इस तथ्य के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए हैं कि यह प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य आवश्यकता है। अतः निर्यातक तीसरे देशों के लिए निर्यात के प्रविष्टि-वार बिल के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए यद्यपि बाध्य हैं, परन्तु इन निर्यातकों ने प्राधिकारी के लिए प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए तरजीह नहीं दी है।

- ध. डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 11.3 के तहत प्राधिकारी दायित्व से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों के दावे और उनके तहत अपेक्षित विश्लेषण का जहां तक संबंध है, इस बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण और वर्तमान निर्धारण वास्तव में प्राधिकारी के द्वारा किए गए ऐसे एक विश्लेषण पर आधारित हैं।
- न. पीओआई के बाद के आंकड़ों के बारे में विचार करने (महत्व देने) का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त हो जाने की स्थिति में आयातों के संभावित व्यवहार को दर्शाने के लिए वर्तमान अवधि में आयातों की मात्रा पूर्णतः और उत्पादन एवं खपत के संदर्भ काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, वर्तमान आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं। पीओआई के बाद विश्लेषण केवल ऐसी स्थिति में ही करना अपेक्षित होता है जहां पर पीओआई में आयात की मात्रा नकारात्मक हो अथवा पीओआई में आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नकारात्मक हों। चूंकि, पीओआई में वर्तमान मामले में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं और वर्तमान पीओआई में आयातों की मात्रा भी चूंकि काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पीओआई के बाद के आंकड़ों की जांच करना जरूरी नहीं है।
- त. प्राधिकारी को अंतिम समीक्षा जांच में शुल्क ढांचे में बढोत्तरी करने के लिए अधिकार नहीं होता है। इस तथ्य के बारे में यह सूचित किया जाता है कि इस पर उपयुक्त रूप से प्राधिकारी के द्वारा विचार किया जाता है और यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित शुल्क की मात्रा में संशोधन करने के लिए यह मौजूदा पद्धति के समनुरूप है।

घ. निष्कर्ष

109. पूर्ववर्ती पर विचार करने के उपरान्त प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि:

- क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं अपनी सामान्य कीमत से कम कीमत पर भारत को निर्यात की गई हैं;
- ख. घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है;
- ग. पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ड. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

110. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा में कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों से पाटित कार्यों से हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग में गिरावट पर नियंत्रण होगा तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक साधन बनाकर रख सकेंगे।
111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः पाटन के अनुचित पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय उद्योग में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी तरह से सीमित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ढ. सिफारिशें

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी पक्षकारों के लिए अधिसूचित की गई थी तथा पाटन, क्षति और कारक लिंक के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्यातकों, आयातकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारक लिंक के बारे में जांच की शुरुआत करते हुए तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाना जारी रखना पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए आवश्यक है।
113. अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का नीचे बताए स्वरूप और तरीके से आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने हेतु इसे जरूरी समझते हैं।

114. कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन के कम मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर यथा मूल्य पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। इसलिए प्राधिकारी निश्चित शुल्कों के रूप से उपाय लगाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, चीन जन गण से मूलतः अथवा निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्मों के आयातों पर शुल्क के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क उस तारीख से लगाने की सिफारिश की जाती है जिस तारीख से केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है।

ण. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

115. प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद का मूल्य स्तर प्रभावित हो सकता है। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा में कमी नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों से पाटित कार्यों से हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग में गिरावट पर नियंत्रण होगा तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता भी आपूर्ति के दो अथवा अधिक साधन बनाकर रख सकेंगे। पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय उद्योग में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः कायम है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः पाटन के अनुचित पाटन के अनुचित व्यापार कार्यों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय उद्योग में खुली और स्पष्ट प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी तरह से सीमित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। उपभोक्ता भी आपूर्ति के दो अथवा दो से भी अधिक साधन बनाकर रख सकेंगे।

त. निष्कर्ष और सिफारिश

116. हितकर पक्षकारों के द्वारा किए गए दावों, उपलब्ध कराई गई सूचना तथा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के विश्लेषण सहित उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तथा हितकर पक्षकारों के द्वारा की गई घोषणा के बाद विवरण निवेदनों के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि:
- संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आती रहती है। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और सार्थक हैं।
 - घरेलू उद्योग के निष्पादन में विभिन्न पैरामीटरों के अनुसार सुधार हुआ है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को हो रही पाटन क्षति को रोका गया है।
 - पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में कीमत में पर्याप्त रूप से कमी होने की संभावना है।
 - संबद्ध देश के पर्याप्त अधिशेष क्षमताएं हैं, संबद्ध देश के निर्यातक अधिक निर्यातोन्मुखी हैं, तथा निर्यात ऐसी कीमत पर किया जाता है, जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को काफी सकारात्मक दर्शाता है, इस तथ्य को मानते हुए प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क वापस लेने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।
 - इसलिए, प्राधिकारी एक यथा मूल्य शुल्क के रूप में पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश करते हैं जो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सीआईएफ मूल्य की प्रतिशतता के रूप में निकाला जाएगा। तदनुसार, नीचे बताए अनुसार शुल्क को कॉलम 9 में निर्दिष्ट प्रतिशतता को लागू करके प्राप्त राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क चीन जन गण से मूलतः अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समस्त आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्षक/	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	सीआईएफ मूल्य का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण	तैशान फाइबर ग्लास इंक.	तैशान फाइबर ग्लास इंक.	33.11
2	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जूशी ग्रुप चेंगडू कं. लि.	मैसर्स जूशी ग्रुप चेंगडू कं. लि.	24.59
3	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स जूशी जियुजियांग कं. लि.	मैसर्स जूशी जियुजियांग कं. लि.	24.59
4	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण	मैसर्स चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन (सीपीआईसी)	मैसर्स चोंगकिंग पोलीकॉम्प इंटरनेशनल कारपोरेशन (सीपीआईसी)	20.46
5	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण	सीरियल नंबर 1- 4 में उपरोक्त के अलावा अन्य किसी भी संयोजन		47.15
6	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण	चीन जन गण के अलावा कोई अन्य देश	कोई	कोई	47.15
7	7019	*नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	नीचे यथावर्णित ग्लास फाइबर	चीन जन गण के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई	कोई	47.15

(*) ग्लास रोविंग सहित ग्लास फाइबर (एसेम्बल्ड रोविंग (एआर), डायरेक्ट रोविंग्स (डीआर), ग्लास चोप्ट स्ट्रॉन्स (सीएस), ग्लास चोप्ट स्ट्रॉन्स मैट। विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र से बाहर विशिष्ट रूप से ग्लास वूल, ग्लास फाइबर वूल, ग्लास फाइबर इंसुलेशन – ऊन के रूप में, ग्लास यार्न, ग्लास वूवन फैब्रिक, ग्लास वूवन रोविंग्स, चोप्ट स्ट्रॉन्स थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए बैट्री सेपरेटर में प्रयुक्त माइक्रो ग्लास फाइबर, सरफेस मैट/सरफेस वील/टिश्यू, वैट चोप्ट स्ट्रॉन्स और कमफिल (अल्कालीरोधी ग्लास फाइबर कंक्रीट री-इंफोर्समेंट के लिए)।

117. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुँच मूल्य का सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्कों के द्वारा यथानिर्धारित मूल्य से मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के तहत समस्त सीमा शुल्क शामिल होते हैं।

118. इस अंतिम जांच परिणाम से उत्पन्न केंद्र सरकार के आदेश के प्रति एक अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**New Delhi, 6th July, 2016**(Final Findings)**

Subject: -Sunset Review investigation relating to Anti-Dumping Duties imposed on imports of ‘certain glass fibre and articles thereof’ originating in or exported from China PR

A. Background of the Case

F. No. 15/10/2015-DGAD-1. Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation for imposition of anti-dumping duty on imports of certain glass fibre and articles thereof, originating in or exported from the China PR vide initiation notification dated 8th January 2010. The Authority issued the Preliminary Findings on 2nd June 2010 and provisional duties were imposed vide Customs Notifications dated 14th July, 2010. The Authority issued Final Findings on 6th January 2011 and definitive duties were imposed on 4th March 2011. The Authority thereafter initiated a Mid-term review investigation against imports of subject goods from subject country on 19th September 2013 and on the basis of the recommendation of the Authority in its final finding dated 10th February, 2014, micro Glass Fibre with fibre diameter in the range of 0.3 - 2.5 microns was excluded from the ambit and scope of the anti-dumping duty recommended, vide Customs Notification dated 9th May, 2014.

2. And Whereas M/s Owens-Corning (India) Pvt. Ltd. and Owens Corning Industries (India) Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as petitioners) have filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry and have requested for continuation of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.
3. On the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/10/2015-DGAD dated 7th July, 2015 to review the need for continued imposition of the duties in respect of ‘certain glass fibre and articles thereof’, originating in or exported from China (hereinafter referred to as subject country), and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to and inclusive of 13th day of July, 2016, vide Notification No.33/2015-Customs (ADD) dated 13th July 2015.
4. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 1. The Embassy of the China in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2).

2. The Authority provided access to the copies of the non-confidential versions of the applications to the known exporters and the embassies of the subject countries and other interested parties in accordance with Rules 6(3) supra..
3. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known producers/exporters in the subject countries and provided them opportunity to make their views known in writing within forty days thereof in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

- i. Chongqing Polycomp International Corp
- ii. Jushi Group Co. Ltd
- iii. Taishan Fiberglass Inc. Economic Development Zone
- iv. Zibo PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Co Ltd
- v. Shandong Fiberglass Composite Materials Co., Ltd
- vi. Changzhou Tianma Group Co., Ltd
- vii. PPG Sinoma Jingjing Fiber Glass Co. Ltd.
- viii. Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd
- ix. Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co Ltd
- x. Taishan Fiberglass Zoucheng Co., Ltd
- xi. Shandong Aste New Materials Co Ltd
- xii. Shandong Fiberglass Composite Materials Co., Ltd
- xiii. CNBM International Corporation
- xiv. Changzhou Tianma Group Co., Ltd
- xv. China National Materials Industry Import & Export Corporation
- xvi. Shandong Taishan-PDO Glass Fiber Products Co., Ltd
- xvii. Sinoma Jinjing Fiber Glass Co., Ltd
- xviii. Zhejiang Jiashan Glass Fibre Weaving Factory

6. Questionnaire Responses have been received from the following exporters:

- i. Jushi Group Jiujiang Co. Ltd.
- ii. Jushi Group Co. Ltd. Tongxiang
- iii. Jushi Group Chengdu Co. Ltd.
- iv. Chongqing Polycomp International Corporation
- v. Taishan Fibreglass Inc.

7. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit.
8. None of the responding exporters have claimed market economy treatment and have therefore not submitted Market Economy Treatment (MET) questionnaire response.
9. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

- i. Kemrock Industries & Exports Ltd.
- ii. Pentair Water India P Ltd
- iii. Amiantit Fibreglass India Limited
- iv. Sundaram Brake Linings Ltd
- v. Graphite India Limited
- vi. Indore Composite Pvt. Ltd.

- vii. Aksh Optifibre Limited
- viii. Balaji Fibre Reinforcement Pvt. Ltd.
- ix. O. K. Glass Fibre Limited
- x. Jushi (India) FRP Accessories Pvt. Ltd.
- xi. Sky Fibreglass Solutions Pvt. Ltd.
- xii. Aarvi Composites Pvt. Ltd.
- xiii. Kush Synthetics Private Limited
- xiv. Advance Textiles & Materials Private Limited

10. Importer Questionnaire Response was received from one importer namely Jushi (India) FRP Accessories Pvt. Ltd.
11. The following users/importers have filed submissions though without a detailed Questionnaire response. Submissions made by these parties have also been taken into account in the present determination.
- i. M/s. UP Twiga Fiberglass Ltd
 - ii. M/s. Urja Products Pvt Ltd.
 - iii. M/s. Saertax India Pvt Ltd.
12. After initiation of a copy of the initiation notification was also sent to the following other known domestic producer of the subject goods, namely, M/s. Goa Glass Fibre Limited. The company extended support to the sunset review application and have provided their injury information. However, the information received was at much belated stage and the data furnished by M/s. Goa Glass Fibre Limited has not been considered for injury determination.
13. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2014 to March, 2015. The examination of trends in the context of injury analysis covers the periods April 2011-March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the POI.
14. The Authority has relied on the DGCI&S data for analysis of dumping and injury analysis. The domestic Industry has furnished data as per the secondary source namely IBIS at the time of initiation and later supplemented it with DGCI&S data.
15. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).
16. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India, as per its consistent practices, so as to ascertain if anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury, if any, to the domestic industry.
17. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 23rd December, 2015, which was attended by the interested parties. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally.
18. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and considered relevant by the Authority, have been addressed in this final Finding Notification.
19. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producers and subject exporters was carried out to the extent deemed necessary.

20. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
21. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used 'best information available' and has treated such parties as non-cooperative.
22. A disclosure statement was issued on 23.6.2016 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. Time up to 29.06.2016 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
23. '****' in this Final Finding Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
24. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.61.69 = 1 US\$.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions by the Domestic Industry

25. The following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - i. There is no known difference in product produced by the petitioner and exported from the subject countries. Both products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc.
 - ii. Wet chopped strands do not have different physical and chemical properties and instead bear the same properties as that of other kinds of glass fibre. Moreover, the variation is not so significant as to render them different products. Different uses for wet chopped strands do not make it a different product as end use substitutability can never be seen as a criteria for like product determination.
 - iii. The petitioner was producing wet chopped strands earlier and the same has been discontinued due to commercial viability. This product type is being produced by other domestic producer and therefore this product type cannot be excluded from the scope of the investigation.
 - iv. M/s. Owens Corning's have stated that they are not manufacturing Wet Chopped Strands. M/s. Goa Glass Fibre Ltd. has stated that they have the capability to produce dry and wet chopped strands. The wet chopped strands were being produced by them till last year but they have stopped because of non-remunerative prices and if prices are better they will be able to produce in future as they have the capabilities.
 - v. A new advanced glass fibre product called Cemfil is an *alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement*, CEMFIL is a brand name of Owens Corning and not manufactured in India. At the time of original investigation, Alkali Resistant Glass was not excluded, as the product type was neither being imported from subject country nor there was any domestic production by the Petitioners. Unless a product type is being imported into India, question of exclusion does not arise. In the present investigation period, however, the product type is being imported into India, while still there is no domestic manufacturer for Alkali Resistant Glass in India. The petitioners had requested at the time of initiation to exclude it from the scope of PUC.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

26. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties have made any submissions in this regard:

- i. M/s. UP Twiga Fiberglas Ltd, have stated that wet chopped strands are not like products to the products supplied by the domestic industry. Wet chopped strands are not 'identical or alike to the article under investigation for being dumped in India' and neither do wet chopped strands have "characteristics closely resembling those of the articles under investigation", in terms of Rule 2(d) of the AD Rules and Article 2.6 of the WTO ADA for the reasons below:
- ii. Wet chopped strands have different chemical and physical characteristics as compared to the products produced by the domestic industry. The moisture content in wet chopped strands is in excess of 8% to 12% and glass content up to 88% to 92% whereas normally glass content in chopped strands is more than 96% and moisture cannot exceed in any case more than 2%. Evidence of the difference between wet chopped strands and glass fibre supplied by the domestic industry has been demonstrated based on the specifications provided on the global website of the domestic industry.
- iii. The production process for wet chopped strands differs significantly from that of the chopped strands. The production process for chopped strands includes batching, melting, fiberization, coating and lastly drying. However, for wet chopped strands, the process differs from the stage of fiberization as the moisture requires to be kept in and therefore it cannot be coated or dried.
- iv. The functions and end-uses of wet chopped strands differ significantly from chopped strands. Wet chopped strands are manufacturing or fibre glass tissues or veils and its end-use applications are in carpet tiles, cushions, vinyl flooring, asphalt roofing, shingles, etc. Wet chopped strands are used in wet-processes and in non-woven applications. Evidence in this regard has been provided based on the global website of the domestic industry.
- v. The findings of the Tribunal in *Oxo Alcohols Industries' Association v. Designated Authority* [2001 (130) ELT 58] and *Indian Refractory Makers Association vs Designated Authority*, 2000 (119) E.L.T 319 (Tribunal), make it clear that products not produced by the domestic industry that are of a different grade/type should be excluded from the levy of anti-dumping duty.
- vi. The Authority can exclude products in a sunset review investigation if the need to restrict the scope of the product under consideration is established. In this regard, reliance was placed on the findings of the Authority in *Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Ductile Iron pipes originating in or exported from China PR*; *Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty imposed on imports of PVC Paste Resin originating in or exported from European Union*; *Sunset Review Investigation of anti-dumping duty imposed on imports of Nylon Filament Yarn from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP*.
- vii. It has been stated by the importer that during the public hearing, the domestic industry accepted that it is not producing wet chopped strands in India and further that wet chopped strands are different products from the products manufactured by the domestic industry. The DI also clarified that wet chopped strands cannot be manufactured at its current facility and further that it does not have future plans of producing wet chopped strands in its facility in India.
- viii. It has been mentioned by the importers that M/s. Owens Corning have stopped manufacturing Chopped Strands for all applications from 2015 onwards. They were earlier making Chopped Strands for thermoset application and not for thermoplastic application, that's how Chopped Strands for thermoplastic applications were excluded from the scope of the PUC. Now M/s. Owens Corning have stopped making Chopped Strands for thermoset applications and hence these also should be excluded from the scope of the PUC.

Examination by the Authority

27. The product under consideration in the original investigation was defined as "glass fibre, including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR), glass chopped strands (CS), glass chopped strand mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass

insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue”.

28. In the midterm review investigation, the scope of the product under consideration was modified to exclude “glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue”.
29. The Authority noted the submission of M/s. UP Twiga Fiberglass Ltd, that the scope of PUC should exclude Wet chopped strands as domestic industry does not produce the wet chopped strands. The production process, physical and chemical characteristics and usage of wet chopped strand is different from the product under consideration. Domestic industry has not been able to demonstrate that the subject goods and wet chopped strands are like articles. A specific reference was made to both the producers seeking confirmation regarding the exact items being manufactured by them. M/s. Owens Corning have confirmed that they are not manufacturing Wet Chopped Strands. M/s. Goa Glass Fibre Ltd. has stated that they have the capability to produce dry and wet chopped strands but wet chopped strands were not being produced by them currently because of non-remunerative prices. The Authority notes that in spite of antidumping duty protection the domestic producers have stopped making wet chopped strands therefore the submission of importer/user is correct to the extent that there is no availability of wet chopped strands in India. Thus, the Authority has decided to exclude wet chopped strands from the present scope of product under consideration.
30. As regards the observation of the importer regarding Chopped Strands for thermoset application. A specific reference was made to M/s. Owens Corning seeking confirmation regarding the list of items being manufactured by them. M/s. Owens Corning have confirmed that they are manufacturing Chopped Strands for thermoset applications. In view thereof, it has been decided by the Designated Authority that Chopped Strands continue to be within the scope of the PUC.
31. None of the opposing interested parties have made submissions against exclusion of Cemfil (*alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement*), the Authority therefore decided to exclude this new product type from the scope of the PUC.
32. Thus, the scope of the product under consideration in the present SSR investigation is as follows:
“Glass fibre, including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre with fibre diameter in the range of 0.3 to 2.5 microns, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands and Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement).”

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by the Domestic Industry

33. Following are the submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - i. The Petitioners have submitted that there is one other producer of the subject goods apart from the petitioners, i.e. M/s Goa Glass Fiber.
 - ii. Both the petitioners are related to Owens Corning, USA, which is the parent company.
 - iii. The petitioners have stated that they have not imported the product under consideration from the subject country.
 - iv. Production by the petitioners constitutes a major proportion of Indian production and petitioners therefore satisfy the requirement of standing under the Anti-Dumping Rules and constitute domestic industry.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

34. . There is no submission by any of the opposing interested parties.

Examination by Authority

35. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

36. The application was filed by M/s. Owens-Corning (India) Pvt. Ltd. and Owen Corning Industries (India) Pvt. Ltd. The Authority notes that there is another producer of the subject goods in the country namely M/s Goa Glass Fibre Ltd which has supported the application after initiation of the investigation. M/s Goa Glass Fibre Ltd had filed its information at a much belated stage and therefore the data has not been considered for injury determination. The petitioners have not made any imports from subject countries during POI. The production of the applicant producers constitutes major portion of the total production of the subject goods and therefore, the applicants constitute domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules.

E. MISCELLANEOUS ISSUES

Submissions by the domestic industry

37. Views of the domestic industry in this regard are as follows:

- i. The petitioner has not imported the product under consideration from China.
- ii. Petitioner has imported following kinds/forms of glass fibre product from third countries. The volume and import price is also given below. Further, the price at which these product types are being imported from China during POI is also mentioned below. It would be seen that the price at which petitioner has imported the product from third countries is materially higher than the price at which product has been exported by Chinese producers.

SN	Product type	Imports by Owen			Owens'	Imports from China		
		Volume (MT)	Value (RS)	Price (RS/MT)	Price (RS/MT)	Volume (MT)	Value (RS)	Price (RS/MT)
1	AR/Roving	***	***	***	***	***	***	***
2	CSM	***	***	***	***	***	***	***
3	T-30/DR	***	***	***	***	***	***	***
4	DUCS	NIL	NIL	NIL	--	***	***	***
5	Total	***	***	***		***	***	***

- iii. The petitioner has imported these products at much higher price than China, or the resale price of Petitioner is much higher than China. Since imports have been made by petitioner and further since the petitioner is related to the exporter, under the law, the resale price of these products are required to be considered.
- iv. M/s. Urja Products has made factually incorrect statement. Both E glass fibers and C glass fibers are nothing but part of product under consideration. The product under consideration has been categorized into following categories at the time of original investigations and in the present investigation. By his own admission C glass fibre is much cheaper and if these are allowed to be imported, the domestic industry shall suffer injury.
- v. As regards Saretex India, Saretex is a producer of glass fabric. Petitioner had not included glass fabric within the scope of product under consideration at the time of original investigation. Present case being a sunset review, Petitioner in any case cannot enhance scope of the product under consideration in a review investigation. Further, the value addition in making glass fabric is above 35% and therefore imports of glass fabric cannot be considered as circumvention of anti-dumping duty. Petitioner explored possibilities of filing fresh dumping petition for glass fabric. However, production of the Petitioner alone constitutes below 50% of Indian production

and therefore Petitioner cannot file the petition without association of other domestic producers. Petitioner shall further explore filing of petition with the association of other producers. In any case, merely because glass fabric is being imported into the Country at dumped prices, the same does not imply that the Authority should exclude the product being produced and supplied by the domestic industry. In fact, exclusion of the product type from scope of duty shall not only imply injury to the petitioner domestic industry, but also producers of glass fabric. Glass fabric in any case would continue to suffer injury, as Chinese producers are likely to dump the product in any case.

Submissions by the opposing interested parties

38. Views of the opposing interested parties in this regard are as follows:

- i. The importer has pointed out that the domestic industry has been importing the product under consideration from its global affiliates consistently during the period of investigation and continues to do so even in the period April - October 2015. The imports by the domestic industry are not in small volumes but are rather significant volumes and at prices lower than the imports of the subject goods from subject country in India. The domestic industry has imported approximately 1405 MT of direct roving during the POI at USD 0.84 per kg from the United States. In the same period, an import from China, which was subject to anti-dumping duties at the rate of about 20%, was being imported by the consumer at the cost of around USD 1.03 per kg. The DI has been supplying imported goods to their customers as their own production is not sufficient.
- ii. M/s. Urja Products Pvt Ltd, a manufacturer of Glass fabric, has pointed out that the Domestic industry is only manufacturing glass fibre of coarse tex and the users of finer tex or finer grade are at a disadvantage with the imposition of duties. They have further pointed out that there are two types of configuration namely E glass fibre for electrical grade glass filament and C glass fibres for Chemical resistant glass yarns. The Domestic industry is making rovings only from E glass and that importers should be allowed to import C glass rovings, which are much cheaper, without ADD duty. The imposition of duty will affect the downstream industry as is making Chinese imports more expensive.
- iii. M/s. Saertex India Pvt Ltd, manufacturer of glass fibre fabric, has opposed imposition of ADD on imports of glass fibres on the grounds that there is no ADD on glass fabric. The ADD on glass fibre will make the raw material expensive for manufacture of glass fabric thereby leading to a situation whereby imports of glass fabric will get intensified and all the manufacturers of glass fabric will suffer from cheap imports of fabric. They have therefore requested for removing of duty from glass rovings, which is a raw material for glass fabric or also impose duty on glass fabric which is their finished goods and used for making wind mill blades.

Examination by the Authority

39. The specific submissions made by the opposing interested parties and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

- i. As regards imports by the petitioner company from third countries, the authority notes that these imports are from countries not under investigation. These imports are by the petitioner from their global affiliated producers and therefore under the Rules, authority is required to consider the resale price of the products in order to examine the effect of these imports on the domestic prices. Further, under Rule 2(b), imports of the products from subject countries alone are required to be considered. Imports from third countries are not relevant of the purpose of determining eligibility of the petitioner as a domestic industry. Since imports from these countries are by a company who is related to the exporter, the authority is required to consider the resale price of such products. Information provided by the petitioner clearly shows, that the resale price of these products are much higher than the purchase price.
- ii. As regard E-Glass Fibre and C-Glass Fibre, the authority notes that both are part of the PUC and therefore there cannot be a case for any exclusion of these product types. The authority notes that the petitioner is also selling glass rovings in the market and dumping margin & injury margin have been determined for four different variants of PUC i.e. Direct Rovings, Assembled Rovings, Chopped Strands and Chopped Strand Mats. The PUC has not been identified grade wise or tex wise during the original investigation or the present review investigation.

- iii. As regard imports of Glass Fabrics, the Authority notes that Glass fabric is beyond the scope of PUC in the present case. In case Glass fabric is being dumped by Chinese producers, the same cannot fall within the scope of present investigations. The affected domestic industry must seek relief either under Rule 5 or under Rule 25. The rationale of the Anti-Dumping Duty is to create a level playing field for both, the domestic industry and the foreign exporter. In case the downstream industry/ importer/user intend that there should be duty on their finished goods then it has to be examined separately and it requires filing of an independent separate application which shall be examined on its merits.

F. Market Economy Treatment, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions by the Domestic Industry

40. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. China is a non-market economy country. No country has granted market economy status to China. Further none of the exporters satisfy each and every condition developed from jurisprudence to qualify for grant of market economy status. Thus, the Chinese producers' cost and price cannot be relied upon for determination of normal value.
- ii. India is an appropriate surrogate country for China as it would result in access to accurate and adequate information. Further, India has been considered as an appropriate surrogate country by other investigation authorities too.
- iii. The normal value has been determined accordingly on the basis of cost of production in India, duly adjusted, in view of the fact that the selling price is a loss making price.
- iv. The petitioners have relied upon transaction wise import data provided by DGCI&S for calculation of export price.
- v. In view of significant difference in the cost of and price of various product types, petitioners have determined separate export price for each product type.
- vi. In case of high sea sale transaction, the Authority should not consider the price paid by final consumer. In fact, it should be construed that the questionnaire responses are not complete in these cases.
- vii. EU and USA have held India as an appropriate market economy third country in a variety of cases. There is no reason to reject the observations and determinations of the EC merely because margins determined by them are higher than the margins determined by India. Even though the export price of the product from China to Europe is higher than that to India, the dumping margin in India is lower compared to dumping margin determined by Europe.
- viii. Petitioners have given detailed information consumption, conversion cost and other relevant pricing data to the Designated Authority as per the prescribed formats.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

41. The following are the submissions made by exporters/importers/other interested parties have made any submissions in this regard:

- i. The DA must determine the dumping margin based on the export price of the exporter as it has extended full cooperation in the instant investigation. The export price thus, must be based on the data placed on record by the exporter.
- ii. The normal value for China is inconsistent with the requirements of Annexure I (7) of the AD Rules. The guidance of the Supreme Court in *Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others* clearly states that prices paid or actually payable in India is to be resorted to only as a last resort. India cannot be considered as an "appropriate market economy third country" for computing the normal value for China.
- iii. India cannot be considered as an appropriate market economy third country as such computation would be erroneous owing to the fact that the petitioners and exporters from China PR are completely different entities functioning in India and China PR respectively which mean that there are various functional variations between the two.

- iv. Recourse to prices paid or payable in India is only available when the other two options have been exhausted, which the Petitioner has failed to do.
- v. The Petitioner has failed to propose an analogue country for price computation and this is in direct contravention of the above law point. Imports of the product from the United States can also be used for such normal value determination as the law permits it.
- vi. With regard to high sea sales undertaken, the price paid by final consumer must be considered rather than price provided in the exporter's data.
- vii. Parties must be informed about the selection of such third country so that they may offer their comments about the same.
- viii. Petitioners have failed to provide details regarding raw material prices used, consumption norms, conversion costs, other costs and profits for the normal value determined.

G. Examination of MET Claims and Determination of Normal Value in China PR

42. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information. Questionnaire Responses have been received from the following exporters:

- i. Jushi Group Co. Ltd., Tongxiang
- ii. Jushi Group Jiujiang Co. Ltd.
- iii. Jushi Group Chengdu Co. Ltd.
- iv. Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)
- v. Taishan Fibreglass Inc.

43. However, none of the exporters have chosen to rebut non market economy claim. The Authority notes that in the past years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members.

44. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

45. As per the above provisions normal value in China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.

46. Interested parties have claimed that imports of the product from the United States can also be used for normal value determination, however it is noted that imports from USA constitutes only one type of product. Thus, in the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country the Designated Authority has constructed the normal value in China on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Authority has determined the Normal Value for the subject goods exported by all exporters in China for each product type as detailed below.

Name of the Exporter	Constructed Normal Value
Jushi Group Co Ltd, Tongxiang	*** US\$/Kg
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd	***US\$/Kg
Jushi Group	***US\$/Kg
Chongqing Polycomp International Corporation	***US\$/Kg
Taishan Fibreglass Inc.	*** US\$/Kg
All other exporters/producers	***US\$/Kg

Determination of Export Price

47. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Jushi Group Jiujiang Co. Ltd, China PR claiming that the company is an exporter of the product under consideration. The company has claimed export of the product under consideration to India during the investigation period. The data filed by the exporter in their questionnaire response was verified at their factory and the individual dumping margin to be determined by the Authority for Jushi Group Jiujiang Co. Ltd is mentioned in dumping margin table below.
48. The authority notes that the questionnaire response has also been filed by Jushi Group Zhejiang Co. Ltd, China PR claiming that the company is an exporter of the product under consideration. The company has claimed export of the product under consideration to India during the investigation period. The data filed by the exporter in their questionnaire response was verified and the individual dumping margin to be determined by the Authority for Jushi Group Zhejiang Co. Ltd is mentioned in dumping margin table below.
49. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Jushi Group Chengdu Co. Ltd China PR claiming that the company is a producer of the product under consideration. The company has claimed no export of the product under consideration to India during the period of investigation.
50. The authority notes that the questionnaire response has also been filed by M/s Jushi (India) FRP Accessories Pvt. Ltd, the importer is related to the Jushi Group exporters. They have claimed imports from their related exporter and have given details of all the transactions. The same was verified at their office in Mumbai. However, they could produce only limited documents as many have been destroyed in a fire at their warehouse.

Name of the Exporter	Export Price (US\$/Kg)
Jushi Group Co Ltd, Tongxiang	***
Jushi Group Jiujiang Co., Ltd	***
Jushi Group	***

51. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Chongqing Polycomp International Corporation China PR claiming that the company is an exporter of the product under consideration. The company has claimed export of the product under consideration to India during the investigation period. The data filed by the exporter in their questionnaire response was verified at their factory and the individual dumping margin to be determined by the Authority for Chongqing Polycomp International Corporation is mentioned in dumping margin table below.

Name of the Exporter	Export Price (US\$/Kg)
Chongqing Polycomp International Corporation	US\$ ***/kg

52. The authority notes that the questionnaire response has been filed by Taishan Fibreglass Inc. China PR claiming that the company is an exporter of the product under consideration. The company has claimed export of the product under consideration to India during the investigation period. The data filed by the exporter in their questionnaire response was verified with the original documents and the individual dumping margin to be determined by the Authority for Taishan Fibreglass Inc. is mentioned in dumping margin table below

Name of the Exporter	Export Price (US\$/Kg)
Taishan Fibreglass Inc.	US\$ ***/kg

Export Price for Non-Co-Operative Exporters/ Producers from China PR

53. The Authority has determined the Export Price in respect of non-cooperative exporters from China PR as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Antidumping Rules. Accordingly, after making the due adjustments, the weighted average net export price at ex-factory level in respect of all non-co-operative exporters from China PR has been determined as shown in the table below:

Determination of Dumping Margin

54. After the analysis of the data, the dumping margin is worked out as mentioned in the table below.

Exporter	CNV	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin Range
Units	(US\$/Kg)	(US\$/Kg)	(US\$/Kg)	(%)	(%)
Jushi Group Co. Ltd., Tongxiang	***	***	***	***	45-55
Jushi Group Jiujiang Co. Ltd	***	***	***	***	45-55
Jushi Group	***	***	***	***	45-55
Chongqing Polycomp International Corporation	***	***	***	***	40-50
Taishan Fibreglass Inc.	***	***	***	***	50-60
Non Co-operative Exporter	***	***	***	***	80-90

H.Determination of Injury and Causal Link

Submissions by the domestic industry

55. The domestic industry has *inter alia* made the following submissions with regard to the injury and causal link:

- The dumped imports from the subject country have continued to enter the Indian ports in significant amount despite anti-dumping duty.
- Subject imports are available at prices lower than domestic prices. If the anti-dumping duty is removed, the dumped imports volume shall intensify.
- The imports are undercutting the domestic prices in the POI. Resultantly, the domestic industry will be faced with price depression in the market in the event of cessation of anti-dumping duties. This will result in decline in profits and consequently return on capital employed and cash profits.
- The petitioners have influenced downstream investments in new technology and product applications by growing their customer portfolio and developing new applications for their products. Removal of anti-dumping duty would severely hamper the growth of the domestic industry and its capacity to invest in novel products and applications.
- In case duty is revoked and consequently imports from the subject countries increase, the Domestic Industry would be forced to reduce the prices of the product concerned significantly given the fact that the product concerned is a commodity product.
- Should the Domestic Industry be forced to reduce the prices, its natural impact would be on the profitability of the Domestic Industry. Decline in profits would lead to decline in cash flow and return on investment.
- Should the Domestic Industry choose to maintain its normal price levels, it is likely to lose its sales volume as consumers would increasingly switch over to the imports.

- viii. Should the Domestic Industry prefer to lose sales volumes, it would spell much bigger injury, as decline in sales volume would result in increase in inventories level, decline in production, capacity utilization, and productivity.
- ix. The petitioners have not claimed continued injury but rather recurrence of injury and continuation of dumping in the event of cessation of antidumping duty.

Submissions by producers/exporters/importers other interested parties

56. The following submissions were made by producers/exporters/importers/other interested parties with regard to injury to the domestic industry:

- i. There is a 33% decline in the imports from the subject country in the POI as compared to the base year of the injury period. Further, imports in relation to production have declined from 39% in 2011-12 to 25% in the POI. The trend in imports relative to consumption also exhibits a steep decline, falling from 28% in 2011-12 to 19% in the POI.
- ii. Domestic industry holds 61% of the domestic demand. Imports constitute merely 19% of domestic demand. The imports from the subject country have the ability to impact the performance of the Petitioners as much as the other domestic producers, that hold 12% of the market share, are able to.
- iii. China's import price increased by 27% in the POI as compared to 2011-12. Further, the imports from the subject country hold less than 20% of the domestic demand. Imports from other countries and sales of other domestic producers together hold 24% of the domestic demand. The price of imports made by the Domestic Industry is significantly lower than import price from the subject countries. Therefore, there is no negative price effect with respect to imports from the subject country.
- iv. Domestic industry accepted that decline in the performance in the period 2012-13 on the above parameters was due to a decline in the demand which was due to an impact on the major consumer sectors of the goods. However, post 2012-13 and 2013-14, all the performance indicators improved.
- v. The capacity utilization of the Petitioners is at nearly 90% which is a strong indication of a thriving industry.
- vi. Profits for the domestic industry's operations in the domestic market have increased by 40% in the POI as compared to 2011-12. The cash profits have increased by 13% and the PBIT by 38% in the POI as compared to 2011-12. Even the range of the ROCE has increased to 20-30% in the POI as compared to 2011-12. Companies that have a ROCE of 20-30% cannot be considered as companies that are being injured or being threatened with injury.
- vii. Inventories have declined by nearly 50% in the POI as against 2011-12. In addition, inventory levels have steadily declined over the course of the injury period and the POI.

Examination by the Authority

57. The injury analysis made by the Authority addresses various arguments put forth by the interested parties in their submissions, at relevant places.
58. Rule 11 of the AD Rules read with its Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". While considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
59. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
60. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further,

since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject countries are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

61. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
62. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
63. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

I. Assessment of Demand/Apparent Consumption

64. The Authority has considered the transaction-wise import data procured from DGCI&S for the assessment of volume and value of imports from the subject country and other countries. The Authority has considered sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources to define the demand or apparent consumption of the product in India. The demand so assessed is shown in the following table:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Sales of Domestic industry	MT	49,307	45,114	43,865	49,767
Sales of Other domestic producers	MT	10,000	10,000	11,700	12,400
Imports from Subject country	MT	18,028	16,765	15,087	16,922
Imports from other countries	MT	7,518	4,075	2,687	10,629
Total Demand	MT	84,853	75,954	73,339	89,718

65. It is noted that the demand declined in 2012-13 and 2013-14 as compared to base year and thereafter increased in the POI. Petitioners have submitted that the decline in 2012-14 was for the reason that during this period there was a slowdown in all the major consumer sectors of the subject goods such as Wind Energy, Pipe/Infrastructure industries, telecom industries and automobile industries.

II. Volume Effects of Dumped Imports

Import Volume and Market Share

66. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti-dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

67. The volume of imports of the subject good from the subject country have been analysed as under:

Particulars	UOM	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Imports Volume					
China	MT	18,028	16,765	15,087	16,922
Other Countries	MT	7,518	4,075	2,687	10,629
Total	MT	25,546	20,840	17,774	27,551
Share in Imports					
China	%	71%	80%	85%	61%
Other Countries	%	29%	20%	15%	39%
Total	%	100%	100%	100%	100%
Total Imports in relation to					
Production (DI)	%	35%	32%	24%	37%
Consumption	%	30%	27%	24%	31%
Subject country's imports in relation to					
Indian Production	%	22%	22%	18%	19%
Consumption	%	21%	22%	21%	19%

68. It is seen that imports from subject country are significant though they have declined over the injury period as a result of anti-dumping duty in force. Imports have also remained significant in relation to production and consumption in India.

III. Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

69. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of dumped imports of subject goods from the subject country.

70. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry as per its consistent practices by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The position is as follows:

i. Price Undercutting

71. Price undercutting has been determined by comparing the export price from subject country with the domestic selling price in India of the subject goods for the period.

S. No.	Subject country	Units	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	Import Volume	MT	18,028	16,765	15,087	16,922
2	Landed Value of Imports	Rs./KG	49	54	56	59
3	Net Sales Realization	Rs./KG	***	***	***	***
4.	Net Sales Realization	Rs./KG Indexed	100	103	113	123
5	Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
6.	Price Undercutting	Rs./KG Indexed	100	83	111	132
7	Price Undercutting	%	***	***	***	***
8	Price Undercutting Range	%	25-35	20-30	25-35	30-40

72. It is noted that the landed price of imports is below the selling prices of domestic industry despite existence of anti-dumping duty signifying significant positive price undercutting in the event of cessation of anti-dumping duties leading to injury to the domestic industry.

ii. Price Suppression/ Depression

73. In order to determine whether the imports of the product under consideration are suppressing or depressing the prices of the product under consideration in the domestic market, the Authority has considered the trends in the cost of sales and the sales revenue for the domestic industry as per the data provided by the domestic industry. The relevant information is given below.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Landed Value of Imports	Rs./Kg	49.24	53.73	55.70	59.22
Trend	Index	100	109	113	120
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	116	118	141
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	103	113	123

74. It is noted that both, cost of sales and selling price of the domestic industry, has increased over the injury period. Thus, the imports are not suppressing or depressing the prices of the domestic industry. However, landed price of imports without ADD is even below the level of cost of sales of the domestic industry. Thus, cessation of anti-dumping duties is likely to lead to increase in low priced imports causing significant price suppression and depression in the domestic market.

iii. Price Underselling

75. For the purpose of determining price underselling, comparison has been made between the landed price of imports and non-injurious price. The price underselling margins as under:

Particulars	Unit	China PR
Non Injurious Price	Rs./MT	***
Landed Value (POI)	Rs./MT	59.22
Price Underselling	Rs./MT	***
Underselling	%	*** %
Underselling	% Range	30-40

76. It is noted from the above table that the domestic industry has suffered significant price underselling during the investigation period on account of imports of the subject goods from the subject country.

IV. Examination of other economic parameters of the domestic industry

77. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

78. The various injury parameters as above relating to the domestic industry have been examined as follows:

i. Capacity, production, capacity utilization and sales

79. The table below shows the capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry for the product under consideration during the injury investigation period.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity	MT	89,511	89,511	89,511	89,511
Production	MT	73,241	64,862	72,699	75,369
Captive	MT	5,293	5,890	8,078	8,156
Capacity Utilization	%	82%	72%	81%	84%
Domestic Sales	MT	49,307	45,114	43,865	49,767

80. It is noted that the capacity of the domestic industry increased marginally in 2013-14. Production, capacity utilisation, and domestic sales volume declined in 2012-13 but increased thereafter. The decline in these parameters for the 2012-13 was in view of the decline in demand.

b. Market share in Demand

81. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Subject country	%	21.25	22.07	20.57	18.86
Other Countries	%	8.86	5.37	3.66	11.85
Domestic industry	%	58.11	59.40	59.81	55.47
Other domestic producer	%	11.79	13.17	15.95	13.82
Domestic producers as a whole	%	69.89	72.56	75.76	69.29

82. It is noted that the market share of domestic industry has increased whereas market share of the subject country has declined over the injury period as a positive effect of anti-dumping duty in force.

c. Impact on profit/loss, cash flow and return on capital employed

83. Performance of the domestic industry with respect to the product under consideration has been examined in terms of the profit/loss, cash flow and return on capital employed, as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	118	141
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	113	123
Profit/(Loss) per unit	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	13	79	3
Profit/(Loss) - total	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	12	70	3
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	86	115
ROCE	%	***	***	***	***
ROCE	Range %	5-15	0-10	0-10	0-10

84. The Authority notes that the profit, cash profit and return on investment declined in 2012-13 and increased thereafter in 2013-14. All these parameters have shown a steep downward trend during POI as compared to the previous year.

d. Employment and Wages

85. The position of the domestic industry with regard to employment and wages is as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Employment	No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	95	94
Wages	Rs lakh	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	145	149
Productivity per person per day	Kg.	282	250	294	309

86. Since the domestic industry is a multi-product company, employment is not an indicator of the adverse effect of dumping. It is however noted that employment level of the domestic industry has declined over the injury period whereas wages paid have increased.

e. Inventories

87. The inventory level with the domestic industry has declined as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Average Stock	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	94	76	59

f. Productivity

88. The productivity per day and per employee of the domestic industry has increased over the injury period as can be seen from the table below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	99	103
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	104	109

g. Ability to raise capital investments

89. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has improved during the injury period therefore the domestic industry is in a position to raise capital and investment. Petitioners have however submitted that one of the critical parts of the manufacturing unit (product under consideration) is its furnace and the typical life of the same is around 10 years. The existing furnace at both the petitioners plant are due for rebuild by end of 2016 or early 2017 which would involve an investment of about Rs. 250 crores and with an additional capacity of 30-35 KT. Thus, if the measures are allowed to expire the petitioners' capability to raise the capital investment would be jeopardised.

h. Growth

90. The domestic industry has grown in terms of production, sales volume, market share, profits, return on investment and cash profits after decline in 2012-13. However, the imports continue to enter the domestic market at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
Production	%	-	-11%	12%	4%
Domestic Sales Volume	%	-	-9%	-3%	13%
Cost of Sales	%	-	16%	1%	20%
Selling Price	%	-	3%	9%	9%
Profit/ Loss per unit	%	-	-87%	516%	-97%

i. Magnitude of Dumping

91. Magnitude of dumping, as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry, shows that the dumping margins determined against the subject country continues to be above de minimis and significant.

j. Magnitude of injury and injury margin

92. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry, taking into consideration the cost of production of the domestic industry. The domestic industry contended that the authority should allow return on investment considering that significant investments are already depreciated and therefore either the authority should allow return on investment after considering market value of these investments or at least a higher rate of return. The authority has however followed its consistent practice of allowing 22% return on investment. The non-injurious price of the domestic industry has been compared with the landed value of the subject goods from the subject country to determine the injury margin. The NIP has been determined for various types of PUC namely Direct Rovings, Assembled Rovings, Chopped Strands and Chopped Strand Mats. The injury margin has been worked out as follows:

Particulars	Non-Injurious Price	Landed Value	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin Range
Unit	US\$/Kg	US\$/Kg	US\$/Kg	%	%
Jushi Group Co. Ltd. Tongxiang	***	***	***	***	15-25
Jushi Group Jijiuang Co. Ltd	***	***	***	***	20-30
Jushi Group	***	***	***	***	15-25
Chongqing Polycomp International Corp.	***	***	***	***	15-25
Taishan Fibreglass Inc.	***	***	***	***	20-30
Non Co-operative Exporter	***	***	***	***	40-50

k. Causal Link

93. The Rules mandates the Authority to examine the causal links between the dumped imports and the injury caused to the domestic industry on account of the dumped imports. The following issues have been brought to the notice of the authority and examined as per information available for the non-attribution analysis:
- Contraction in demand:** There has been rise in demand of the product concerned over the injury period. Possible decline in demand cannot be considered as a possible reason of injury to the Domestic Industry
 - Pattern of consumption:** - There is no significant change in the pattern of consumption for the subject goods affecting the conditions of the domestic industry.
 - Conditions of competition:** - The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.
 - Developments in technology:** - The Authority notes that the investigation has not shown that there was any significant change in technology in the manufacturing process or usage of the product
 - Export performance of the domestic industry:** - The volume of exports of the domestic industry has increased during the injury investigation with a slight decline in the POI. In any case, the performance of the domestic industry has been segregated and analysed for its domestic operations only.

l. Conclusion on Injury and Causal Link

94. It is noted that growth of the domestic industry in terms of all economic parameters like production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, cash profits and return on capital employed has been positive. There is thus no adverse effect on the economic parameters of the domestic industry during the POI on account of subject imports. However, there is significant injury on account of dumped imports in terms of price undercutting, underselling, price suppression and depression

m. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

95. The Authority observed that this is a sunset review investigation and the focus of this investigation is to examine the likely scenario of injury if the duties were to be removed, even if there is no current injury. The subject imports have, even though, declined are still entering into the domestic market and dumped and injurious price.

Views of the Domestic Industry

96. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- China is attracting anti-dumping duties imposed by European Commission since 2010. The European Commission has recently enhanced the anti-dumping duty on China by undertaking an interim review and has also imposed anti subsidy duty on imports of subject goods from China. This clearly indicates the intensity at which the goods are being exported by the subject country.
 - Imports have increased by 316% from the base year of the original investigation, whereas demand has increased by 136%. Thus imports have increased more than increase in demand despite existence of anti-dumping duty as can be seen from the below table. It is likely that revocation of duties would lead to further increase in imports and the domestic market being taken away by imports.
 - Dumping Margins determined in previous investigations and present petition are positive and significant. This clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty. In the previous investigation the Authority attributed a dumping margin ranging from 25%-60% for both cooperating and non-cooperating exporters. In the current investigation, the dumping margin determined for all products is 16%.

Producer	Capacity (000 MT)
Jushi Group Co., Ltd	1,000
Chongqing Polycomp International Corp.	448

Taishan Fiberglass Inc. and Taishan Fibreglass (zoucheng) Co., Ltd.	425
Weibo	170
Shandong Fiberglass Composite Materials Co., Ltd.	180
Jiangsu Changhai Composite Materials Co. Ltd.	100
Changzhou tianma group Co. Ltd	30
PPG Sinoma Jingjing Fiber Glass Co.Ltd.	60
Xingtai JinNiu Fiber Glass Co.,Ltd.	60
Jiangsu Jiuding New Material Co,Ltd	70
Total	2543

- iv. Producers of subject goods in the subject country maintain huge capacities. Domestic industry has provided the following information on the estimated capacities of some of producers in China to illustrate the fact of surplus capacities in these countries enabling them to dump the goods in the event of revocation of the duty. Relevant information showing the production capacities with producers from subject country is shown in table below:
- v. The petitioners also relied upon the Global and China Glass Fiber Industry Report, 2012 – 2015 referred to by the European Glass Fiber Producers Association in its application for imposition of countervailing duties continuous filament glass fiber products, the capacity with the producers from China increased to above 4 million MT and the consumption of China was approximately 1,874,000 MT in 2012 much below the level of the productions of the producers from China.
- vi. The petitioners submitted that the average prices at which subject goods are being exported to third countries are much lower than the export price to India as per China Customs data. It thus shows that China is capable of exporting goods at much lower price. Cessation of anti-dumping duty would make the Indian market more lucrative and the producers would start exporting at increased intensity at prices that will cause significant injury to the domestic industry.

Year	India		To World	
	Quantity (MT)	USD/KG	Quantity (MT)	USD/KG
2007	35,165	1.2	7,48,689	1.1
2008	43,277	1.3	8,57,711	1.3
2009	48,420	1.0	6,23,782	1.1
2010	57,505	1.1	8,11,707	1.1
2011	49,329	1.3	8,91,991	1.2
2012	42,934	1.3	9,27,016	1.2
2013	31,114	1.4	9,24,685	1.2
2014	37,806	1.3	9,29,138	1.2

- vii. Public research shows that, in 2012, Chinese production was around 3 million MT. The total available capacity would be much higher than the production level of the subject country. Glass fibre industry is an encouraged industry in China and the production and supply of Glass fibre is expected to further increase as is evidenced by the findings by the EC. Jushi plans to increase its capacity to 1.5 million tons accounting for 25% of the global production and plans to export 50% of it. Taishan fibreglass announced in 2013, its plan to operate a glass fibre furnace capable of producing 80,000 MT/year.

- viii. The petitioners have analyzed the exports from China to third countries as per China customs. It is seen that exports to the tune of 141,388 MT made by China to third countries, are at dumped prices, which is more than the total demand in India. Further, dumped exports by China are significant in relation to production, sales and consumption in India.
- ix. Comparison of the landed price of imports with that of the selling price of the Domestic Industry shows significant price undercutting. Should the present anti-dumping duty be revoked, it is evident that exporters would further increase their exports in the Indian market, given the huge capacities with them, causing injury to the Domestic Industry.

Views of other Interested Parties

97. There is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry based on the factors below:

- i. During the injury period and the POI, imports from subject country have declined steadily both in absolute terms and in relation to production and consumption.
- ii. There is no dumping during the POI and post POI period, there is no likelihood of recurrence of any dumping.
- iii. There is no evidence to establish that there are huge unused capacities in China in regard to production of the subject goods.
- iv. Reference to investigations by the European Commission are not relevant as the duty should be determined based on the facts and data submitted in the instant investigation.
- v. An unsubstantiated table, stating increased capacities in China without any information source does not prove an increase in capacity of exporters. In fact as many as 16 Chinese fiberglass kilns has entered cold repair period and backward capacity was eliminated just before the POI in the current investigation.
- vi. Mere availability of capacity is not a sufficient ground to conclude that there will be likelihood or continuation of dumping and subsequent injury.
- vii. Post POI data is used to analyse the likelihood of continuation or recurrence of dumping an injury. Post POI data is to be analysed only if the Domestic Industry has not suffered injury in the POI.
- viii. The findings of other authorities should not impact Indian Authority and there cannot be a selective approach of adopting European Commission principles and not others.
- ix. Level of current and past dumping margins is irrelevant as the present investigation is for examining injury and dumping for a fresh period.
- x. Imposition of antidumping duty by EU does not imply increased imports in India and there is no evidence for it and that import in India is a fact because of demand supply gap.

Examination by the Authority

98. The Authority has examined the contention of the domestic industry and other interested parties to examine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The following analysis shows whether there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of antidumping duties:

a. Positive dumping margin and injury margin despite anti-dumping duty

99. The Authority notes that even though subject imports have declined over the injury period, the dumping margin and injury margin continues to remain positive. Thus, producers from subject country are likely to intensify dumping and cause injury to the domestic industry in the event of cessation of antidumping duty.

b. Antidumping measure by other country

100. It is noted that European commission has carried out anti-dumping investigations and anti-subsidy investigations and imposed anti-dumping duties and countervailing duties on producers and exporters of the subject goods from

subject country. Imposition of duty has been enhanced through interim review and an expiry review is being currently undertaken. This clearly indicated the inclination of exporters in the subject country to export goods at dumped prices.

c. Dumping Margin determined in previous and present investigations

101. The Authority notes that the Dumping Margin determined in previous investigations and present investigation are significant which indicates likelihood of continuation of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

d. Excess production capacity of the producers

102. Domestic industry has submitted and has placed on record various documents showing high export orientation by Chinese producers and significant capacity availability with these producers. As per records, producers in China have large production capacities for the subject goods, much more than the domestic demand in India. In the event of revocation of existing anti-dumping duties, there is a strong likelihood of dumping of the product in India. Domestic industry has submitted that Glass fibre industry is an encouraged industry in China and the production and supply of Glass fibre is expected to further increase.

e. Price undercutting in the absence of measures

103. The Authority examined the effect of cessation of anti-dumping duty in terms of price undercutting effect on the prices of the domestic industry in the market and its consequent impact on the domestic industry. It is noted that the price undercutting with and without anti-dumping duty is high in the POI. Thus, the Authority notes that it is evident that if anti-dumping duties currently in place are allowed to expire; the imports would cause severe price undercutting which would cause material injury to the Domestic Industry.

f. Exports to India are at prices higher than prices for the rest of the World

104. The Authority has considered the average prices data provided by the Petitioner at which subject goods are being exported to third countries and to India as per China Customs data. It is noted that the average price at which subject goods are being exported by subject country to third countries are lower than the export price to India, which itself is at dumped price. It is thus noted that the exports to third countries are at much lower dumped price. Cessation of anti-dumping duty is likely to make the Indian market more lucrative and the producers from subject country would start exporting at increased intensity at prices that will cause significant injury to the domestic industry.

J. Causal Link

105. Under Section 9A (5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. The investigation has shown that the imports were at dumped prices, the domestic industry has once again suffered injury and the volume is likely to increase if antidumping duty were allowed to be ceased. Notwithstanding, the Authority has examined whether other listed known factors could have caused or are likely to cause injury to the domestic industry.

- a) Imports from third countries: - Imports from third countries are either negligible in volume or higher in prices. Third country imports are unlikely to cause injury to the domestic industry.
- b) Demand for the product: - There is no contraction in demand for the product under consideration and therefore claimed injury to the domestic industry cannot be due to possible contraction in demand.
- c) Changes in the patterns of consumption: - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

- d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers: - There is no trade restrictive practice which can contribute to the injury to the domestic industry.
- e) Developments in technology: - It is noted that the technology for production of the product has neither undergone any material change. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury.
- f) Performance of other products produced and sold by the domestic industry: - The domestic industry is a multi-product company. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration only.
- g) Export performance: - the domestic industry has claimed injury only on the account of the domestic operations. The authority has segregated export performance at appropriate places.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

Views of the Domestic Industry

106. The comments submitted by DI have been summarized and are as below:

- i. UP Twiga cannot be entertained as an interested party for the reason that the company has not filed importer's questionnaire response. This directly emanates from the decision of the Hon'ble CESTAT in the matter of Merino Panel Products Ltd. vs. Designated Authority. Had the importer filed questionnaire response well in time, it could have been perhaps treated as an interested party.
- ii. The product under consideration has been reported under customs classification other than the specified, and further since there are a number of product types which are within the scope of the PUC and a number of product types which are beyond the scope of the product under consideration. Therefore, the Designated Authority has been requested to specify in duty table the product under consideration which should attract duty regardless of the customs classifications under which goods are being cleared by the importers. Anything mentioned in the para relating to "product under consideration" but not stated in duty table is likely to get ignored while issuing notification by the Ministry of Finance. Further, the Customs authorities at the port consider and rely upon the notifications issued by the MOF.
- iii. The petitioner has not imported the product under consideration from China. Petitioner has imported glass fiber from third countries.
- iv. Both E glass fibers and C glass fibers are nothing but part of product under consideration. The product under consideration has been categorized into various categories at the time of original investigations and in the present investigation. By the importer's own admission, when glass fiber is much cheaper and if these are allowed to be imported, the domestic industry shall suffer injury.
- v. Petitioner had not included glass fabric within the scope of product under consideration at the time of original investigation. Present case being a sunset review, Petitioner in any case cannot enhance scope of the product under consideration in a review investigation. In any case, merely because glass fabric is being imported into the Country at dumped prices, the same does not imply that the Authority should exclude the product being produced and supplied by the domestic industry.
- vi. The imposition of anti-dumping has led to improvement in the performance of the domestic industry in terms of production, sales, capacity utilization, profitability. However, imports of the product under consideration increased during the POI in absolute terms, and have remained significant in relation to production and consumption of the subject goods in India. Increase in imports is much more than the increase in demand.
- vii. Price undercutting without anti-dumping duty is significantly positive. There is significant injury on account of dumped imports in terms of price undercutting, underselling, price suppression and depression.

- viii. It has been repeatedly held by the CESTAT and the Designated Authority that in case the price undercutting, dumping margin and injury margin are positive and with the volume of imports as high as the present, the only inescapable conclusion shall be that the withdrawal of anti-dumping duty shall lead to injury to the domestic industry.
- ix. Petitioners are almost at the last stage of finalizing their plans to invest over Rs. *** Crores in rebuilding the furnace. This is likely to expand their capacity up to *** MT in India. The cost of production and NIP of the domestic industry is likely to increase the moment these investments are commercialized, given that the Designated Authority has considered historical costs and return on the same for determining NIP.
- x. EU is at present conducting a sunset review in the product under consideration for imports from China (in fact, the scope of the product under consideration in Europe is larger than India).
- xi. This further establishes likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xii. The average prices at which subject goods are being exported to third countries are lower than the export price to India. Further, exports to India are at dumped prices.
- xiii. Domestic industry submitted that anti-dumping duty may be imposed as percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country (ad valorem form of duty).

Views of other interested parties

107. The brief summary of the comments submitted by opposing interested parties (exporter/importer/users) is as below:
- i. The total demand differs from that of the petition. There is significant difference between the figures recorded by the Authority and those provided by the petitioner. This indicates that the initiation of the sunset review investigation was based on flawed petition. Respondent is unaware of the reason for the change in the data sets that have been relied upon by the Authority in the investigation.
 - ii. As per original data in petition, demand assessment while there was 1% decline in demand during the POI, the import volume from China has seen a 33% decline during the POI. As per the revised data also, the demand has increased by 6%, whereas the imports from China has decreased by 6% during the POI as compared to the base year 2011-12. In view of these trends there is no case for continuing with the existing antidumping duties against China.
 - iii. There are two types of configuration of fibreglass: (1) Filament made from E-glass and (2) Filament made from C-glass. E-glass is electrical grade glass filament and C-glass fibres are chemical resistant glass fibre yarns. Rovings made from C-glass yarn are much cheaper than rovings made from E-glass. The Indian producers are not manufacturing C-glass roving and import of C-type of rovings should be allowed. Levy of anti-dumping duty in India has rendered Chinese rovings more expensive so China has started to export fabrics/ woven rovings made out of their cheap C glass rovings without attracting ADD and killing the woven fabric industry. The duties should therefore be removed from entire roving industry.
 - iv. The imports share from China has decreased while that of other countries has increased. The imports from China have seen a decline even when there is an increase in demand; also imports from other countries have substantially increased by 41% during the POI No volume injury caused to domestic industry.
 - v. In spite of the alleged dumping from China PR, the Domestic Industry is selling the subject goods at a price which is higher than the NIP determined by the Authority. Thus, significant injury in terms of price underselling is incorrect.
 - vi. Capacity, production, capacity utilization, domestic sales, market share in demand, profit/ loss, cash flow and ROCE, profitability has increased over the injury period as noted by the Authority.
 - vii. Given the fact that NIP is lower than the net sales realization of the Domestic Industry, the determination of injury margin or presence of positive injury margin is irrelevant.
 - viii. With regard to Causal Link, the Authority disregarded the following arguments of the Exporter:

- a. Volume and value of imports from countries other than China PR (Egypt, Mexico, United States and Thailand) may be causing injury to the Petitioners. Import prices, especially from Egypt and United States are around the same range as import prices of subject goods from China PR.
 - b. Demand of subject goods had fluctuated heavily throughout the injury period. Despite recovery of demand in period of investigation, there was meager increase in imports from China.
 - c. There has been a sharp decline in profitability of the Petitioners on account of its export performance, which suggests that injury, if any, is self-inflicted.
- ix. The action by the European authorities is irrelevant with respect to the present investigation. The Authority has not considered that currently expiry review by the European authorities is in process and it is entirely possible that anti-dumping duty is withdrawn after such review.
- x. There is no evidence in the disclosure regarding the fact that Chinese producers have large production capacities and the glass fibre industry is an encouraged industry in China.
- xi. The Authority notes that exports to India are at higher prices than the rest of the world. However, the source data has not been placed on the public file for a closer scrutiny by the Exporter. Furthermore, as per the information provided by CPIC, the exports to third countries are priced higher than exports to India, both in the period of investigation and in six months post investigation period.
- xii. The wording for the exclusion is for all types of glass woven rovings and chopped may be clearly paraphrased to avoid future confusion.
- xiii. The methodology for determination of Non-Injurious Price that has been adopted by the Hon'ble Designated Authority is unclear. The details of the working may be shared with the interested parties. The Authority has wrongly granted 22% rate of return to the domestic industry. In determining the non-injurious price for domestic industry, the statute provides for a reasonable rate of return to be included. In the case of Indian Spinners Association v. Designated Authority reported at 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.) the Hon'ble CESTAT highlighted the importance of considering the historical rate of return of the domestic industry to determine the RoCE to be adopted in arriving at the non-injurious price.
- xiv. The Authority has erroneously determined the raw material cost based on consumption over the POI. The Authority is mandated to consider "the best utilization of raw materials by the domestic industry, over the past three years period and the period of investigation".
- xv. The Authority has noted in the disclosure statement that under the Rules the Authority is required to consider the resale price of the products in order to examine the effect of these imports on the domestic prices. However, the legal provision on the basis of which Authority has concluded that such an examination is required is questionable.
- xvi. By the findings of the Authority itself, there is a decline of volume of imports from China PR in absolute numbers. At the same time, there is an increase in the imports from other countries. The Authority has accepted in paragraph 73 of the disclosure statement that imports from the subject country are not suppressing or depressing prices of the domestic industry.
- xvii. The Authority is requested to take into account the impact that imports from other countries have on the performance of the domestic industry. In particular, the share has increased from 3.66 % in 2013-14 to 11.85% in the POI. There has been a significant increase with respect to imports from other countries.
- xviii. Capacity, production, capacity utilization, domestic sales, market share in demand, profit/loss, cash flow and ROCE, profitability have increase over the injury period as noted by the Authority.
- xix. With regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- a. Imposition of duties by other authorities should not impact the decision of the Indian Authority.

- b. There has been no increase in the volume of imports from the subject country over the last 4 years. As a matter of fact, imports from other countries have increased substantially mainly due to imports by the domestic industry itself.
 - c. Merely the presence of large capacities does not translate into surplus capacities. In particular, the Chinese companies have been functioning at high utilization figures which indicates that there is no reason to conclude that imports to India will increase if the duty is removed.
 - d. The fact that China is exporting to third countries is no indication that it is engaged in dumping. In addition, Respondent submits that Owens Corning also has an affiliate company in China which by implication will also be contributing to this alleged dumping to third countries.
- xx. The Authority must undertake 'likelihood determination' as per obligations under Article 11.3 in accordance with certain parameters. Post POI data must be taken into consideration while undertaking an analysis. It is crucial that this requirement is complied with in the present matter because no injury has been proven to exist and the Authority must carry out the due projections to justify any extension of duty.
 - xxi. The power of the Authority in a sunset review is restricted only to the continuation or withdrawal of Duty and not for its enhancement. Without prejudice to the contention that there is no dumping of the subject goods and that the subject goods are not causing any injury to the domestic industry, the purpose of a sunset review is to examine whether continuation of anti-dumping duty is warranted in light of the likelihood of dumping and injury due to imports of the product under consideration.
 - xxii. An anti-dumping duty can only be extended if there's an affirmative finding that cessation of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Continuation of duty by SSR is an exception, rather than a rule.
 - xxiii. The DI cannot cater to the domestic demand, therefore imports from other countries including subject countries becomes imperative. Even after the imposition of the anti-dumping duty the imports have more or less remained the same especially due to the demand supply gap.
 - xxiv. M/s Taishan made limited exports of an off grade product known as 'Waste' which is a scrap and off cut of CSM from the production process. The sales price of Waste is much lower than other grades. Quantity of Waste exported to India is less than 2% of the total exports made by Taishan in the POI. Waste should be excluded from the scope of product under consideration due to vast differences in physical characteristics as well as price compared to subject goods.
 - xxv. Though Taishan has not claimed MET status it has worked under market economy conditions. Taishan has requested the authority to calculate Normal Value based on the data given by Taishan.
 - xxvi. Since there is no output VAT applicable on exports, the producer cannot collect and output VAT from the overseas buyers. However, it can claim VAT rebate against the input VAT so paid. The Authority should take the aforesaid into consideration and the respondent disputes the calculation of the dumping margin.
 - xxvii. The demand of the subject goods has increase in absolute terms, the domestic sale has increase, the domestic sales of other domestic producers have increased, and the volume of imports from China has decreased. Market share of imports from China has reduced from the base year in the period of investigation whereas the share of imports from other countries has increased.
 - xxviii. There is no price undercutting caused due to imports from China. The selling price of the domestic industry has increased over the injury period. However, it has erroneously concluded that the landed price of imports without ADD is even below the level of cost of sales of the domestic industry.
 - xxix. The laded value of imports of the subject goods from China has shown an increasing trend. The price underselling, if any, is due to other factors. Per unit as well as total profit, ROCE, cash profits, all are positive. There is no injury as per any of the economic parameters of the domestic industry.

Examination by the authority

108. The issues/ contentions raised by all the interested parties and domestic Industry have been dealt with in detail in the preceding paragraphs, however, for sake of clarity they are being again addressed in following paragraphs:

- a. As regards the contention that the data provided in the petition & submissions made by petitioners are different from the data contained in the disclosure statement, the authority clarifies that the petition was based on secondary sources data procured by the petitioner; while the Authority has relied upon DGCI&S transaction wise data obtained subsequently during the course of investigations. Information in the disclosure statement is based on verified information, whereas the information in the petition was based on petitioners' claims. The purpose of conducting investigations is to establish correct facts. Further, since the present case is a sunset review, the authority is required to consider volume of imports for the purpose of undertaking likelihood analysis, as opposed to an original investigation wherein the volume of imports is relevant to determine whether imports have caused material injury to the domestic industry.
- b. As regard E-Glass Fibre and C-Glass Fibre, the authority notes that both are part of the PUC and therefore there cannot be a case for any exclusion of these product types. The authority notes that the petitioner is also selling glass rovings in the market and dumping margin & injury margin have been determined for four different variants of PUC i.e. Direct Rovings, Assembled Rovings, Chopped Strands and Chopped Strand Mats. The PUC has not been identified grade wise or tex wise during the original investigation or the present review investigation.
- c. As regards demand for the product under consideration, the Authority notes that the overall demand for the product over the injury period shows increasing trend. Further, imports from China have shown a decline till 2013-14 but picked up an increase during POI. Since present investigation is a sunset review investigation, existence of injury to the domestic industry on all parameters is not a pre-requisite for determining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The authority is not required to determine whether the domestic industry suffered material injury. The authority is required to determine likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in case of cessation of existing anti-dumping duties. The volume of imports from China during POI constituted 18% of demand/consumption in India, and therefore the volume in itself is quite high and indicative of the likely situation of intensification of imports in the event of cessation of anti-dumping duty.
- d. As regards decline in market share of China in total imports, the Authority notes that share of imports in relation to production and consumption in India during POI was higher than the previous year. Thus, despite anti-dumping duty in force, the volume of imports from China has remained significant in relation to production and consumption in India.
- e. As regards, the contention that the Domestic Industry is selling the subject goods at a price which is higher than the NIP determined by the Authority, is not correct. The authority notes that the selling price of the domestic industry is below the NIP determined by the Authority. In any case, the mere fact that the domestic industry is selling a product at a price above the NIP does not imply unlikelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The Authority notes that the landed price of imports from China is below the cost of production, selling price and NIP of the domestic industry, implying that the domestic industry shall be forced to reduce the price in the event of cessation of anti-dumping duty and thus affecting the profitability of the domestic industry steeply and the domestic industry shall suffer financial losses. It is also clarified that the price underselling has been seen by comparing NIP with landed price of imports. The Authority therefore considers that positive injury margin in a situation where domestic industry is already selling at a price above NIP is quite relevant.
- f. As regards the contention that economic parameters relating to domestic industry have shown improvement, the Authority notes that analysis in the disclosure statement and in the present findings does not conclude that the performance of the domestic industry has deteriorated in respect of these parameters; nor deterioration in these parameters over present injury period is a pre-requisite for holding that cessation of anti-dumping duty shall lead to injury to the domestic industry. Since the product was attracting anti-dumping duty, the performance of the domestic industry in respect of these economic parameters have shown improvement. What is however required to be seen is that if the anti-dumping duty in force is withdrawn, whether the performance of the domestic industry shall be maintained at the present levels, or, the performance of the domestic industry shall deteriorate. Should the present duties be withdrawn and if the domestic industry maintains its prices, it follows that the consumers shall find Chinese product far cheaper than what it is at present. Considering significant unutilized capacities in China, it

therefore follows that the importers/ consumers shall resort to increased imports from China. Resultantly, the domestic industry shall face decline in sales and consequently market share, production, capacity utilization, profits, return on investment and cash flows. Alternatively, if the domestic industry decides to reduce the prices in order to bridge the gap between domestic and imported product in the event of cessation of anti-dumping duty, the same shall imply that the profitability of the domestic industry shall steeply deteriorate and the domestic industry shall suffer financial losses. Consequently, return on investment and cash flow will also deteriorate. The return on investment and cash profit shall also become negative. Thus, cessation of anti-dumping duty shall lead to deterioration in performance of the domestic industry both in respect of volume and price account.

- g. As regards the contention of the interested parties with regard to causal link, the Authority notes that as far as imports from Egypt and US are concerned, the import price from USA largely represent the imports made by Petitioner. The authority notes that what is relevant here is whether imports from non-subject countries have caused injury to the domestic industry and therefore in view of relationship between the two parties, the Authority has considered sale price of the domestic industry. The import price from US and sale price of the petitioners were examined in detail and it is seen that the sale price of the petitioners are far higher than the import price from China. In any case, there is no evidence that the imports from third countries benchmarked the prices of the domestic industry. If imports from third countries were not benchmarking the prices of the domestic industry, these imports could not have caused injury to the domestic industry.
- h. As regards demand for the product, the Authority notes that while there was some fluctuation in demand, overall demand for the product in India shows a positive trend. Further, even when Indian industry produces at full capacities, the Indian industry shall meet only 69% of the demand for the product in the country. Remaining demand in any case will have to be met through imports. Thus, it is not a case where performance of domestic industry has got impacted due to fluctuation in demand or decline in demand. The authority also notes that it is the consistent practice of the authority that the Indian industry need not have capacities sufficient enough to meet the entire demand for the product in the country. Ability to meet the demand for the product in the country has not been seen as a necessary pre-requisite either for imposition or for continuation of anti-dumping duty. It is also noted that the domestic industry has submitted that they are rebuilding the furnace to expand production capacity in substantial quantities with considerable investments.
- i. As regards sharp decline in profitability of the Petitioners on account of its export performance, the Authority has considered domestic sales, profits, return on investment and cash flow of the domestic industry only for domestic operations. Therefore possible deterioration in export performance in any case has not been considered while examining injury to the domestic industry. The present determination is based on likelihood of injury to the domestic industry. The investigation has shown that the injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of existing anti-dumping duty. The authority has not based its determination on a mere possible or plausible situation. The authority has based its determination on the investigation and the verified facts. The verified information of the domestic industry shows that the landed price of imports is materially below the selling price, cost of production and NIP of the domestic industry. Thus cessation of anti-dumping duty shall result in significant price undercutting and underselling. The conclusion has been drawn by the Authority based on positive evidence relating to cost of production, selling price, NIP determined by the authority and landed price of imports. The domestic industry provided financial data substantiating that the landed price of imports has been below cost of production, selling price, NIP determined by the authority. Thus, the determination is based on facts and not merely allegation, conjecture or remedy possibility.
- j. As regards anti-dumping duty in force in Europe and sunset reviews initiated by Europe, the Authority notes that the very fact of existence of anti-dumping duty, anti-subsidy duty in Europe and the present initiation of anti-dumping and anti-subsidy investigation against China shows that the product was being dumped in the European market. The Authority notes in this regard that the notice of initiation by European Commission states that the dumping margin calculated is significant for the country concerned. The Commission has further found that "the current import level of the product under review from the country concerned to the Union is likely to increase due to the existence of unused capacity of the manufacturing facilities of the exporting producers in the country concerned and the apparent attractiveness of the EU market as evidenced by an increasing demand for and high prices of the product under review".

- k. As regards evidence of surplus production capacities in China, the Authority notes that the petitioners submitted information showing that Chinese producers have capacities to the extent of 25,43,000 MT and Chinese producers are exporting the product in third countries to the extent of 9,29,138 MT as per the approximate details available in public domain knowledge. The interested parties have not refuted the claim of the petitioner domestic industry by providing contrary evidences. The claim of domestic industry with regard to exports to third countries is based on China customs data and the same also has not been refuted. Further, the notice of initiation issued by the EC also states that the import level of the product under review from the China to the Union is likely to increase due to the existence of unused capacity of the manufacturing facilities of the exporting producers in the country concerned, which is based on the petition filed by European domestic industry before EC.
- l. As regards export price from China to third countries, Authority notes that the comparison of export price from China to India and third countries is based on China customs data and the said information is publically available. The Authority further notes that likelihood examination cannot be limited to a particular exporter and is required to be done in respect of exports from China to various global markets by various producers. It is also noted that none of the exporters have established that their exports are unlikely to cause injury to the domestic industry.
- m. As regards determination of NIP, it is clarified that the NIP has been determined on the basis of methodology consistently applied by the Authority. The capital employed has been determined on the basis of book value of the assets. It is consistent practice of authority to grant 22% return on capital employed for determining NIP. The domestic industry in fact contended that the authority should grant higher return in view of peculiar nature of this industry and considering that the present furnace of domestic industry is due for replacement which shall cost huge investment by the domestic industry and therefore ROI should reflect this investment. The authority has however not considered higher rate of return as demanded by the domestic industry. At the same time, authority considers that it would not be appropriate to grant lower rate of return in the present case. Further, it is clarified that the NIP has been determined at ex-factory level.
- n. As regards proper wordings of excluded products, the authority agrees with the contention of Jushi and has appropriately modified the scope of the product under consideration.
- o. It is clarified that the raw material cost consumption factors have been considered in accordance with annexure-III to the rules. The authority has considered the best utilization of raw materials by the domestic industry over the past three year's period and the period of investigation rates.
- p. As regards the contention that there is decline in volume of import from China and increase in imports from third countries, the authority notes that the volume of imports from China has shown some decline from 2012-13 to 2014-15. Imports from China however increased in the present POI. At the same time, imports by other countries have increased in POI. However, these third country imports are largely by the petitioner from its affiliates, which have been examined in detail and it is found that it cannot be concluded that these third country imports have caused injury to the domestic industry.
- q. As regards the contentions of absence of suppression and depression, the authority notes that the present situation is required to be seen along with the fact that anti-dumping duties is in force. Absence of suppression and depression when anti-dumping duties is in force does not imply no likelihood of suppression or depression when the ADD is allowed to cease. In fact, domestic industry has not suffered suppressing and depressing effect of import on domestic industry price because of anti-dumping duties in force.
- r. The interested parties have contended that mere presence of large capacities in China is insufficient and does not amount to surplus capacities. The interested parties have also contended that Chinese companies have been functioning at high utilized rates. The authority however notes that the information on records shows significant unutilized capacities with the Chinese producers. The authority notes in this regard that none of the responding exporters have provided bill of entry wise details of their export to third countries, despite the fact that this is a mandatory requirement prescribed by the authority. Thus, while the exporters are obliged to provide bill of entry wise details of exports to third countries, these exporters have preferred not to provide relevant information to the authority.

- s. As regards the contention of the interested parties concerning obligation of authority under Article 11.3 of the WTO ADA and the analysis required thereunder, the authority notes that the disclosure statement and present determination in fact is based on such an analysis carried out by the authority.
- t. As regards consideration of Post POI data, the authority notes that the volume of imports in current period is significant enough in absolute terms and in relation to production and consumption in order to show likely behaviour of imports in the event of cessation of anti-dumping duties. Further, the dumping margin and injury margin in respect of present imports are positive. The post POI analysis is required to be undertaken only in a situation where volume of import in the POI is negligible or the dumping margin and injury margin in respect of imports in the POI is negative. Since the dumping margin and injury margin in the present case in the POI itself is positive and further since volume of imports in present POI is significant enough, the authority considers that it is not necessary to examine post POI data.
- u. As regards the fact that the Authority is not empowered to increase the duty structure in sunset review investigation, it is stated this considered appropriate by the Authority and is consistent with the existing practice to modify the extent of duty based on the facts and circumstances of the case.

L. CONCLUSION

109. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:
- a. The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
 - b. The domestic industry has suffered material injury;
 - c. There is a likelihood of recurrence of injury in case of cessation of Anti dumping duties.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

110. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.
111. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

N. RECOMMENDATIONS

112. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that continued imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury.
113. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of advalorem anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
114. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends continuation of advalorem anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Therefore, the Authority recommends imposition of the measure in terms of fixed duties. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the duty table is recommended to be imposed from the date of issue of Notification by the Central Government, on imports of PVC Flex Films originating in or exported from China PR.

1. **Indian industry's interest and other issues**

115. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the continuation of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

1. **Conclusion and Recommendation**

116. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority and on the basis of above analysis including analysis of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and post Disclosure Statement submissions made by the interested parties, the Authority concludes that:
- The subject goods from the subject country continue to enter the Indian market at dumped prices. Dumping margin and injury margin are positive and significant.
 - The performance of the domestic industry has improved in various parameters and imposition of anti-dumping duty has prevented dumping causing injury to the domestic industry.
 - Price undercutting is likely to be significantly positive in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - The fact that subject country has significant surplus capacities, exporters from subject country are highly export oriented, and exports made are at a price which is showing significantly positive dumping margin and injury margin, the Authority determines that in the event of withdrawal of the anti-dumping duties, there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry.
 - Therefore, Authority recommends continuation of imposition of anti-dumping measure as an ad valorem duty, to be worked out as a percentage of the CIF value of imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, antidumping duty equal to the amount arrived at by applying the percentage indicated in Col 9 of the duty as below is recommended to be imposed on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

Duty Table

Sl. No	Heading	Description of goods	Specification	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	% of CIF Value
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	China PR	Taishan Fiberglass Inc.	Taishan Fiberglass Inc.	33.11
2	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	China PR	Jushi Group Jiujiang Co. Ltd.	Jushi Group Jiujiang Co. Ltd	24.59
3	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	China PR	Jushi Group Co. Ltd., Tongxiang	Jushi Group Co. Ltd., Tongxiang	24.59
4	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	China PR	Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)	Chongqing Polycomp International Corporation (CPIC)	20.46

5	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	China PR	Any combination other than mentioned in Sl. No. 1 to 4 above		47.15
6	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	47.15
7	7019	*Glass Fibre as described below	Glass Fibre as described below	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	47.15

(*) glass fibre, including glass roving (assembled rovings (AR), direct rovings (DR)), glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings, chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue, wet chopped strands and Cemfil (alkali resistant glass fibre for concrete reinforcement).

117. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

118. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority